ASHOKA

SMA - Ashoka Express Publication

अशोका एक्सप्रेस

Member : CNSI, Delhi निर्वाण प्राप्त गीता भारती राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

Website :-www.ashokaexpress.com YouTube ashokaexpress

E-mail :-ashoka.express@live.com ashokaexpress

संपादक :- विजय कुमार भारती

प्रबंधक :- सज्जन सिंह

● वर्ष: 29 ● अंक : 30 ● नई दिल्ली ● 16 से 22 अगस्त 2026 ● पृष्ठ : 8 ● मूल्य : 2 रूपये

थोक मुद्रास्फीति जुलाई में मामूली घटकर 9.78%

दिल्ली से नोएडा तक बारिश, लोगों को मिली गर्मी-उमस से राहत; मौसम विभाग का अलर्ट

दिल्ली/ग्रेटर नोएडा । शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले घने बादल छा गए और कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। इस बारिश ने पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को तत्काल राहत दी। वहीं नोएडा से लगे दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई। सुबह से ही उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल थे, लेकिन दोपहर में मौसम सुहाना हो गया। करीब एक घंटे तक लगातार झमाझम बारिश होने से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को नोएडा में बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारों की संभावना पहले ही जताई थी। ग्रेटर नोएडा में भी गरज के साथ हुई तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई। हालांकि, इस बारिश के कारण जगह-जगह जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद तेज हवाएं चलने लगीं और गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी और चिपचिपी उमस से शहरवासी काफी परेशान थे। बारिश के कारण वातावरण में ठंडक घुल गई और मौसम बेहद खुशनुमा हो गया। तापमान में गिरावट आने से लोगों ने राहत की सांस ली और घरों से बाहर निकलकर ठंडे मौसम का लुत्फ उठाया। नोएडा और यमुना सिटी में बीते गुरुवार को दिनभर चिपचिपी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल रहा। दो दिन पहले हुई झमाझम बारिश के बाद लोगों को उम्मीद थी कि तापमान में गिरावट आएगी और झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि, मौसम ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है। बृहस्पतिवार को नोएडा का अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में आर्द्रता 83 और यमुना सिटी में 80 प्रतिशत रही। पूर्वानुमान के मुताबिक, नोएडा में आज हल्की और कल तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

विभाजन का दर्द किया याद: पीड़ितों के संघर्ष-बलिदान को किया नमन, कार्यक्रम में 1947 की दर्दनाक कहानियां जीवंत

नई दिल्ली । 1947 के विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को कमजोर करने वाली मानसिकता को दोबारा कभी पनपने नहीं दिया जाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर जनपथ रोड पर डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कपिल मिश्रा ने विभाजन पीड़ितों के संघर्ष, साहस और बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम में 1947 के विभाजन के दौरान हुए विस्थापन, बिछड़ने और संघर्ष की स्मृतियों को सामने रखा गया। कपिल मिश्रा ने कहा कि विभाजन की विभीषिका को वर्षों तक दबाने और भुलाने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने यह सुनिश्चित किया है कि उस दौर का दर्द, बलिदान और

उससे मिले सबक कभी भुलाए न जाएं। उन्होंने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस करोड़ों पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से सीख लेने का अवसर है। कपिल मिश्रा ने कहा कि जो समाज अपने इतिहास, बलिदानों और उनसे मिले सबक को भूल जाता है, उसका भविष्य मजबूत नहीं हो सकता। विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ देश को यह प्रण दोहराना होगा कि भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को कमजोर करने वाली सोच दोबारा जगह न बना सके। कार्यक्रम में विभाजन की घटनाओं को केवल इतिहास के एक अध्याय के तौर पर नहीं, बल्कि उससे जुड़े मानवीय दर्द और संघर्ष के रूप में सामने लाया गया।

कला के जरिए नई पीढ़ी तक पहुंची विभाजन की कहानी

विशेष आयोजन में संगीत, रंगमंच और वीडियो को एक साथ जोड़कर 1947 के विभाजन की कहानी प्रस्तुत की गई। सोनम कालरा और उनकी टीम ने 'स्टोरीज ऑफ सेपरेशन' की संगीतमय प्रस्तुति दी। इसमें अलगाव, विस्थापन, बिछड़ने और उस दौर की स्मृतियों से जुड़ी कहानियों को कलात्मक तरीके से पेश किया गया। प्रस्तुति के जरिए यह दिखाने का प्रयास किया गया कि राजनीतिक फैसलों का असर आम लोगों के जीवन पर किस तरह पड़ा।

मानवीय कहानियों को याद रखना जरूरी

कपिल मिश्रा ने कहा कि संगीत, रंगमंच और वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कार्यक्रम इतिहास की उन मानवीय कहानियों को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास है, जो विभाजन की त्रासदी के पीछे छिपे दर्द और संघर्ष को सामने लाती हैं। उन्होंने आयोजन के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और कलाकारों का भी आभार जताया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने गोल्डन टेम्पल गुरबानी प्रसारण पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली। एक प्राइवेट टीवी चैनल को गोल्डन टेम्पल से गुरबानी के प्रसारण या दोबारा प्रसारण से रोकने की मांग वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की याचिका पर कोई अंतरिम आदेश देने से शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। एसजीपीसी और पीटीसी नाम के एक चैनल ने कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गैलेक्टिक टेलीविजन एंड कम्युनिकेशंस के खिलाफ

हाई कोर्ट का रुख किया था। एसजीपीसी ने याचिका में तर्क दिया कि गोल्डन टेम्पल से गुरबानी के प्रसारण का कॉपीराइट उनके पास है। संस्था ने कहा कि गैलेक्टिक टेलीविजन, 10 सेकंड की देरी के साथ ही सही, इसका प्रसारण करके उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। फिलहाल, गोल्डन टेम्पल से गुरबानी का प्रसारण एसजीपीसी के यूट्यूब चैनल और पीटीसी पर किया जाता है।

15 अगस्त से पहले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट, सुरक्षा सख्त

नई दिल्ली । स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली में सख्त सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. लाल किले के बेहद करीब मौजूद पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेकर पुलिस ने भी अपनी निगरानी और तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में 11 अगस्त को दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने स्टेशन और उससे जुड़े संवेदनशील हिस्सों का गहन निरीक्षण किया. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को परखने के साथ ड्यूटी पर तैनात जवानों को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए.

अधिकारियों ने लिया सुरक्षा तैयारियों का जायजा

स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए विशेष पुलिस आयुक्त विजय कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त (ट्रांसपोर्ट रेंज) मिलिंद डुमरे और पुलिस उपायुक्त बी. भारत रेड्डी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन थाना क्षेत्र पहुंचे. वरिष्ठ अधिकारियों ने कई घंटे तक इलाके में मौजूद महत्वपूर्ण स्थानों और संवेदनशील पॉइंट्स का जायजा लिया. निरीक्षण का मकसद मौके पर तैनात पुलिस बल की वास्तविक तैयारियों को परखना और किसी भी संभावित चुनौती से निपटने की क्षमता का आकलन करना था.

सुरक्षा समीक्षा केवल थाना परिसर तक सीमित नहीं रही. अधिकारियों ने छाता रेल, पार्सल क्षेत्र, आसपास की इमारतों की छतों और प्रमुख ड्यूटी प्वाइंट्स का निरीक्षण किया. इन स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी और उनकी जिम्मेदारियों की भी समीक्षा की गई. संवेदनशील स्थानों पर किसी संदिग्ध

गतिविधि की पहचान और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की व्यवस्था को खास तौर पर परखा गया.

सीसीटीवी से लेकर एंट्री-एग्जिट तक सुरक्षा तंत्र की जांच

निरीक्षण के दौरान स्टेशन की निगरानी व्यवस्था भी वरिष्ठ अधिकारियों के फोकस में रही. सीसीटीवी सर्विलांस, एक्सेस कंट्रोल और सुरक्षा से जुड़े दूसरे परिचालन इंतजामों की समीक्षा की गई. अधिकारियों ने यह जानने की कोशिश की कि किसी अचानक पैदा होने वाली कानून-व्यवस्था या सुरक्षा चुनौती के दौरान मौके पर मौजूद बल कितनी तेजी से स्थिति को नियंत्रित कर सकता है.

लावारिस सामान दिखे तो देरी नहीं, तुरंत होगी कार्रवाई

थाना स्टाफ को स्वतंत्रता दिवस तक विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. भीड़ वाले स्थानों और संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी के साथ जरूरत के अनुसार सघन चेकिंग करने को कहा गया है. पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कोई संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि या लावारिस वस्तु नजर आने पर तत्काल सूचना साझा करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

आरपीएफ और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर चलेगी निगरानी

रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए दिल्ली पुलिस को रेलवे सुरक्षा बल और संबंधित अन्य एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने को कहा गया है. 15 अगस्त तक संयुक्त जांच और निगरानी अभियान के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है. इसके साथ ही रेल संपत्ति की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के बीच संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी पुलिस के सामने रहेगी.

पुरानी दिल्ली स्टेशन बना अहम सुरक्षा केंद्र

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की लोकेशन इस पूरी सुरक्षा कवायद को और महत्वपूर्ण बना देती है. स्टेशन लाल किले के नजदीक स्थित है और स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले के आसपास सुरक्षा का स्तर सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक रहता है. ऐसे में रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों, आसपास के इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी किसी भी संभावित जोखिम को समय रहते रोकने की रणनीति का हिस्सा है.

एफसीआरए विवाद

विपक्ष के कड़े विरोध के चलते विदेशी अंशदान विनियामक अधिनियम संशोधन बिल (एफसीआरए) संयुक्त संसदीय समिति के विचारार्थ भेज दिया गया है। मानसून सत्र हंगामे के चलते पूरी तरह से धुल गया है। यद्यपि संसद ने कुछ बिल बिना चर्चा के पास कर दिए लेकिन एफसीआरए बिल पर पक्ष-विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई। देश में विदेशी फंडिंग पर निगरानी कोई नई घटना नहीं है। एफसीआरए पहली बार 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय लागू किया गया था। बाद में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इस कानून को और सख्त बनाया था। हर देश की सरकारें यह सुनिश्चित करती हैं कि विदेशी धन का इस्तेमाल केवल उसके घोषित उद्देश्यों के लिए किया जाए न कि किसी राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए। सरकार को पता होना चाहिए कि कौन किसे और किस मकसद से फंड दे रहा है ताकि विदेशी धन का गलत इस्तेमाल न हो। भारत में विदेशी फंड के दुरुपयोग की कहानियां किसी से छिपी हुई नहीं हैं। सत्ता के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाने के लिए यहां की संस्थाओं और व्यक्तिगत रूप से लॉबिंग करने वाले गिरोहों से जुड़े लोगों को विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल देश में कई वर्षों से धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है। अरब देशों और अन्य इस्लामिक देशों से मदरसों और मुस्लिम संगठनों को खूब पैसा मिलता रहा है और पश्चिमी देशों द्वारा चर्च को भारी फंड मिलता रहा है जिसका इस्तेमाल लोगों को इसाई धर्म में लाने का षड्यंत्र चल रहा है। कौन नहीं जानता कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के विरोध में एनजीओ का आंदोलन विदेशी फंडिंग से ही चलाया गया। मोदी सरकार के शासनकाल में विदेशी फंड प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों पर समय-समय पर कड़ी कार्रवाई की गई। उनके एफसीआरए पंजीकरण रद्द किए गए। मोदी सरकार द्वारा एफसीआरए बिल लाए जाने का उद्देश्य इतना है कि अब एनजीओ को स्पष्ट करना होगा कि विदेशी धन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होगा और वह किन क्षेत्रों के लिए काम करेंगे। सवाल देश की सुरक्षा, संप्रभुता और लोकतांत्रिक ढांचे का भी है। भारत कोई 'बनाना' रिपब्लिकन तो है नहीं। इसलिए निगरानी तंत्र होना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि बिल को लेकर विवाद क्या है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दक्षिण भारत के राजनीतिक दल इस बिल को अल्पसंख्यक विरोधी करार दे रहे हैं। मोदी सरकार ने विदेशी चंदा कानून में पहले ही कई संशोधन पारित करवाकर नियमों को सख्त किया है लेकिन प्रस्तावित बिल इन नियमों से कहीं आगे बढ़कर प्रस्ताव करता है। जिसमें विदेशी फंडिंग से बनी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया जाएगा, भले ही सर्टिफिकेट खत्म हो गया हो। बिल के तहत दान पाने वाली संस्था का रजिस्ट्रेशन न केवल तब खत्म हो सकता है जब सरकार उसे रद्द कर दे, बल्कि तब भी जब रिन्यूअल से मना कर दिया जाए, अप्लाई न किया जाए, या पुराना सर्टिफिकेट खत्म होने से पहले मंजूरी न दी जाए। जैसे ही ऐसा होगा, ऑर्गनाइज़ेशन के विदेशी फंड और उनसे जो बनाया गया था वह अपने आप सरकार की तय अथॉरिटी को चला जाएगा। प्रॉपर्टी तभी वापस आएगी जब ऑर्गनाइज़ेशन सरकार द्वारा तय समय के अंदर दोबारा रजिस्टर कराएगा, ऐसा न करने पर वह हमेशा के लिए चली जाएगी। बिल के मुताबिक, विदेशी पैसे से बनी कोई बिल्डिंग, जिसका कुछ हिस्सा ही विदेशी पैसे से बना है, उसे पूरी तरह से अपने कब्ज़े में ले लिया जाएगा। फिर ऑर्गनाइज़ेशन को वह हिस्सा वापस पाने के लिए अप्लाई करना होगा जिसकी पेमेंट विदेशी पैसे से नहीं की गई है। बिल डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील करने की इजाज़त देता है, लेकिन सिर्फ़ इस बात के खिलाफ कि अथॉरिटी बाद में प्रॉपर्टी के साथ क्या करती है। रिन्यू करने से मना करने पर अपील नहीं की जा सकती और मना करने से पहले ऑर्गनाइज़ेशन को सुनवाई का हक़ नहीं होगा। असल में, क्योंकि अथॉरिटी सेंटर के निर्देशों पर काम करती है, इसलिए सेंटर लाइसेंस वापस लेने, प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने और फिर उस पर कब्ज़ा करने वाली बॉडी को निर्देश देने के लिए अस्पष्ट कारणों का इस्तेमाल कर सकता है। इन प्रस्तावित प्रावधानों का अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थाएं विरोध कर रही हैं। केवल मिजोरम, नगालैंड में इसाई धार्मिक संगठन सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि विदेशी फंड से ही उनके स्कूल-कालेज और अस्पताल चलाए जाते हैं। तमिलनाडु विधानसभा में तो सर्वसम्मति से इस विधेयक को वापिस लेने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। अमेरिका के सांसद और संगठन भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। भारत में 52 हजार से अधिक एनजीओ रजिस्टर्ड हैं लेकिन सक्रिय 15 हजार के लगभग हैं। 22,498 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। विरोध का बिन्दु यह भी है कि कुछ हिन्दू धार्मिक संगठनों को एफसीआरए लाइसेंस दे दिया गया है। अब जबकि विधेयक को जेपीसी के पास भेज दिया गया है तो इस पर आम सहमति कायम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि आम सहमति की उम्मीद कम है। विधेयक में ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए कि अल्पसंख्यक धार्मिक संगठनों को अपनी बात रखने का मौका मिले और उन्हें अपील करने का अधिकार मिले ताकि कानून के दुरुपयोग की संभावनाएं न के बराबर हो। एनडीए सरकार के समर्थक नगालैंड के मुख्यमंत्री नेक्यूरियो, मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा से लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री के.के.संगमा ने भी एफसीआरए के कड़े प्रावधानों को लेकर अपनी चिंता से केन्द्र को अवगत कराया है। देखना होगा कि जेपीसी में आम सहमति कैसे कायम होती है।

जेन ज़ी और.....

देश में, पूरे देश में भले ही न हो पर देश के एक बड़े भू भाग में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान और एनसीआर में एक बहुत बड़ा संस्कारी आंदोलन चल रहा है। यह हर वर्ष सावन के महीने में चलता है, मतलब होता है। यह संस्कारी आंदोलन है, कांवड़ यात्रा। यह जंतर मंतर जैसे संस्कार विहीन आंदोलन से बिल्कुल ही अलग है। ये जो जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था बिल्कुल संस्कार विहीन था। संस्कारहीन जेन ज़ी द्वारा किया गया था। उस आंदोलन को करने वाली जेन ज़ी इन सरकार जी के समय में ही समझदार हुई है। सरकार जी के समय में ही आंखें खोलीं और इसने सरकार जी के ही भाषण सुने हैं। उसने देखा है कि सरकार जी स्वयं पहले के सरकारजियों को कितना खुल कर गालियां देते हैं, संसद तक में देते हैं। उसने देखा और सुना कि सरकार जी की पार्टी के नेता कितनी भद्दी भाषा बोलते हैं। और जो उसने देखा और सुना, वही ग्रहण कर लिया। सरकार जी एक नेता की माता को जर्सी गाय, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की विधवा को कांग्रेस की विधवा बोलते हैं। सरकार जी की पार्टी के लोग उसी महिला को बार बाला बोलते हैं। सरकार जी उसी माँ के बेटे को हाइब्रिड औलाद की गाली देते हैं। सरकार जी एक राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री को मंच से टपोरियों की तरह, दीदी! ओ दीदी! पुकारते हैं। संसद में विपक्ष की किसी नेता को सूपर्णखा बोला जाता है तो किसी सांसद को आतंकवादी। देश के पहले प्रधानमंत्री को अय्याश बोला जाता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं। बड़ों को जो करते देखते हैं, सीख लेते हैं। बल्कि उत्साह में और बढ़ कर करते हैं। लेकिन बात तो हम कांवड़ यात्रा की कर रहे थे। उसकी वजह से देश के उस हिस्से की जान सांसत में रहती है जहाँ जहाँ से ये कांवड़ यात्रा गुजरती है। आप चलते चलते कांवड़ या कांवड़िये से टकरा गए तो आपके व्हीकल की तोड़ फोड़ तो होगी ही, आप की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। पुलिस और सेना के जवानों तक को ये लोग नहीं छोड़ते हैं। छात्र-छात्राओं के ले जा रही स्कूल वैन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। सरकारें इनसे खुश रहती हैं। खुश रहती हैं क्योंकि ये महंगाई पर सवाल नहीं उठा रहे होते हैं, ये बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे होते हैं। इनको शिक्षा से भी कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए सरकार इनकी सेवा में जुटी रहती हैं। वह सरकार जिसे सड़क पर दस-पंद्रह मिनट की नमाज से दिक्कत होती है, इनके लिए बाकी लोगों के रास्ते बंद कर देती है। जगह जगह कावड़ शिविर लगाती है। मुफ्त खाना, मुफ्त ठहरना और मुफ्त का नाच गाना। पुलिस के आला अफसर, मंत्री और मुख्यमंत्री इन पर पुष्प वर्षा करते हैं। जिन जिन जिलों से ये गुजरते हैं, सरकार वहाँ के स्कूल कॉलेज आठ दस दिन के लिए बंद कर देती है। क्या पता, इन कांवड़ियों का गुस्सा स्कूल वैन पर ही उतर जाए। स्कूल बंद होने से ध्यान आया, हमारी सरकार तो एक लाख के करीब सरकारी स्कूल परमानेंटली बंद कर चुकी है। पढ़ना है तो अपने खर्चे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ो। सरकार का काम सिर्फ महंगाई बढ़ाना है, जीएसटी और इनकम टैक्स वसूलना है, और हाँ, जरा सी बारिश में बह जाने वाली सड़कों पर टोल टैक्स वसूलना है। बाकी पढ़ाई-लिखाई, रोजगार ढूंढना और इलाज कराना है तो अपने आप करो। और हाँ, सरकार ने एक काम और अपने हाथ ले लिया है। वही काम जो पहले बेईमान व्यापारी किया करते थे, अब सरकार अपने आप करती है। वह काम है मिलावट करना। पेट्रोल में एथनोल और डीज़ल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाने के बाद खबर है कि अब पीएनजी में बायोगैस मिलाई जाएगी।

संसद के सामने नई चुनौती

आशुतोष झा।

बड़े दिनों बाद विपक्ष और खासकर कांग्रेस को एक सफलता मिलने का अहसास हो रहा है। उसकी जो चाहत थी, वह पूरी हो गई। मानसून सत्र करीब-करीब धुल गया और परिसीमन विधेयक भी नहीं आ पाया। द्रमुक के विपक्षी खेमे से बाहर जाने और कांग्रेस के खिलाफ तीखे तेवर अपनाने, शरद पवार गुट की एनसीपी के बदले सुर, तृणमूल में टूट जैसी कई घटनाओं ने कांग्रेस को आशंकित कर रखा था। ऐसे में छात्र आंदोलन के रूप में उसके हाथ बटेर आ गया। कुछ सत्तापक्ष की रणनीति भी मात खा गई और विपक्ष की मंशा पूरी हो गई, लेकिन विपक्ष को यह सोचना होगा कि लंबी राजनीति में ऐसे अवरोध की रणनीति बहुत काम नहीं आती। परिसीमन तो संवैधानिक व्यवस्था है और वह होगी ही। वह कांग्रेस नहीं रोक पाएगी और उसमें अभी विपक्षी खेमे में खड़े कई दल भी साथ देंगे। लिहाजा सफलता को स्थायी बनाना है तो शोर-शराबे की राजनीति से आगे जाकर विमर्श की ऐसी राजनीति सीखनी और करनी होगी, जिससे जनता उसके नैरेटिव को समझ सके। विपक्ष ने रणनीति के तहत सत्र को नहीं चलने देने का मन बना लिया था, फिर भी यदि सत्तापक्ष सदन चलाने की सार्थक पहल करता तो विमर्श में शायद आगे दिखता। जिस तरह पूरा सत्र हठधर्मिता के कारण बाधित हुआ, वह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। विपक्ष अगर सार्थक मुद्दों पर सकारात्मक जीत हासिल करे तभी लोकतंत्र की सफलता है। वैसे तो 2014 के बाद से कई बार और 2024 के बाद से अधिकतर यही देखा गया है कि संसद सत्र से ठीक पहले कुछ ऐसे मुद्दे उभरते हैं, जिन्हें विपक्ष लपक लेता है। जंतर-मंतर पर सीजेपी का आंदोलन ऐसा ही एक मुद्दा था। इससे पहले उस भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर किसान आंदोलन खड़ा करने की तैयारी थी, जो वस्तुतः अभी फाइनल ही नहीं हुआ है। ऐसे आंदोलनों के पीछे कौन सी ताकत काम करती है, यह समझा जा सकता है। मानसून सत्र की शुरुआत में भी जब अवरोध उत्पन्न हुआ तो किसी को

विपक्ष अपने हठ पर अड़ा रहा और सरकार की ओर से इसे तोड़ने की बहुत कोशिश नहीं हुई। बात सिर्फ इस मानसून सत्र की दशा से चिंतित होने की नहीं है। संसद का चलना सिर्फ सरकार और विपक्ष के हित-अहित की बात नहीं है। यह जनता के हित की बात है, क्योंकि इस शोर में भी कई विधेयक बिना चर्चा के पारित हुए। बात सिर्फ इस मानसून सत्र की दशा से चिंतित होने की नहीं है। संसद का चलना सिर्फ सरकार और विपक्ष के हित-अहित की बात नहीं है। यह जनता के हित की बात है, क्योंकि इस शोर में भी कई विधेयक बिना चर्चा के पारित हुए। सरकार चाहती तो विदेशी चंदे से जुड़े एफसीआरए को भी इसी तरह पारित करा सकती थी, लेकिन व्यापक विचार-विमर्श के लिए संयुक्त समिति को भेज दिया गया। चिंता की बात यह है कि जनता के मन में उठ रहे सवाल संसद में पूछे ही नहीं जा रहे। परिसीमन का भूत पूरी तरह नहीं भागा है। यह अटकल है कि तेजी से बदलते तकनीक के युग में जब एसआइआर का काम लगभग पूरा हो चुका है और जनगणना का मोटा स्वरूप आंका जा सकता है तो भावी परिसीमन से जुड़ा काफी काम कम समय में किया जा सकता है। जो काम सामान्यतः ढाई से तीन वर्ष का होता है, वह डेढ़ साल में भी हो सकता है तो सरकार शीतकालीन सत्र तक भी एक बार फिर से बिसात बिछा सकती है।

हैरत नहीं हुई, क्योंकि पहला हफ्ता शोर-शराबे में ही जाने की एक परंपरा सी बन गई है, लेकिन यह सत्र थोड़ा अलग रहा। विपक्ष ने इसका चलना अपने लिए अस्तित्व की लड़ाई बना लिया और डर था पसिसीमन विधेयक का। सरकार की ओर से संकेत था कि संविधान संशोधन के लिए जरूरी नंबर से कुछ अधिक उसके पास हैं। इसके चलते अलग-अलग मुद्दों को तूल देकर सत्र ही नहीं चलने दिया गया। बार-बार मुद्दे बदले गए, पर ध्येय एक था-संसद रोको। न रहे बांस, न बजे बासुंरी। कांग्रेस को पता है कि परिसीमन तो होगा, लेकिन अभी रोक लिया तो 2029 के चुनाव तक एक बाजी और लगाने का बल बचा रहेगा। अगर लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो गई तो बचे हुए दो-ढाई साल में ज्यादा मशक्कत न हो पाएगी। सीटों का बदला हुआ स्वरूप अलग रंग दिखाएगा और 2029 गंवाने का अर्थ है 20 साल सत्ता से बाहर रहना, जो जाहिर तौर पर कांग्रेस और उसके कई नेताओं के लिए अस्तित्व बचाने की बात होगी, लेकिन क्या कांग्रेस को इसकी याद दिलानी होगी कि देश के बहुत बड़े हिस्से से वह 30-40 वर्षों से भी ज्यादा वक्त से सत्ता से बाहर है। अगर संविधान के अनुच्छेद 81 और 170 के तहत 2027 की जनगणना के आधार पर परिसीमन पर हुआ तो कांग्रेस के सामने संकट होगा। कांग्रेस फिलहाल हिमाचल के साथ दक्षिण के तीन राज्यों में सत्ता में है। क्या तब कांग्रेस संविधान को चुनौती देगी, क्योंकि वैसी स्थिति में तो सपा भी परिसीमन के समर्थन में खड़ी होगी और राजद एवं उत्तर भारत के अन्य दल भी। कांग्रेस को यह समझना होगा कि अकेला परिसीमन चुनावी जीत-हार का कारण नहीं हो सकता। विजय के लिए परिश्रम और धैर्य की जरूरत होती है और वर्तमान कांग्रेस में यह गुण थोड़ा कम ही है। मानसून सत्र जिस तरह गुजरा, उसका पूरा दोष विपक्ष पर ही नहीं डाला जा सकता। सरकार से भी चूक हुई और वह उसे समय रहते ठीक भी नहीं कर सकी। छात्र आंदोलन का मुद्दा वाजिब था। सरकार इसका आकलन नहीं कर पाई कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जंतर-मंतर पर पहुंचेगे। इस समझने में भी देर हुई कि इस आंदोलन का विपक्षी दलों ने साथ दिया। यही कारण है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन विवाद नहीं थमा। छात्र तो झारखंड में भी उद्वेलित हैं। वहां आंदोलन का स्वरूप वैसा नहीं रहा, जैसा दिल्ली के जंतर-मंतर पर था। जंतर-मंतर जैसी हिंसा रांची में नहीं हुई। सत्तापक्ष को समय रहते हुए दिल्ली में उन राजनीतिक ताकतों को बेनकाब करना चाहिए था, लेकिन उससे चूक हो गई। संसद में तीन हफ्ते तक विपक्ष मुद्दे बदल-बदल कर शोर करता रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में आकर जवाब देने की पेशकश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। यदि सरकार प्रस्ताव देने के बजाय चर्चा की शुरुआत करा देती तो शायद विपक्ष भी हारकर चर्चा में हिस्सा लेने को मजबूर होता या बेनकाब हो जाता। विपक्ष अपने हठ पर अड़ा रहा और सरकार की ओर से इसे तोड़ने की बहुत कोशिश नहीं हुई। बात सिर्फ इस मानसून सत्र की दशा से चिंतित होने की नहीं है। संसद का चलना सिर्फ सरकार और विपक्ष के हित-अहित की बात नहीं है। यह जनता के हित की बात है, क्योंकि इस शोर में भी कई विधेयक बिना चर्चा के पारित हुए। सरकार चाहती तो विदेशी चंदे से जुड़े एफसीआरए को भी इसी तरह पारित करा सकती थी, लेकिन व्यापक विचार-विमर्श के लिए संयुक्त समिति को भेज दिया गया। चिंता की बात यह है कि जनता के मन में उठ रहे सवाल संसद में पूछे ही नहीं जा रहे। परिसीमन का भूत पूरी तरह नहीं भागा है। यह अटकल है कि तेजी से बदलते तकनीक के युग में जब एसआइआर का काम लगभग पूरा हो चुका है और जनगणना का मोटा स्वरूप आंका जा सकता है तो भावी परिसीमन से जुड़ा काफी काम कम समय में किया जा सकता है। जो काम सामान्यतः ढाई से तीन वर्ष का होता है, वह डेढ़ साल में भी हो सकता है तो सरकार शीतकालीन सत्र तक भी एक बार फिर से बिसात बिछा सकती है। यह डर विपक्ष को फिर से मानसून सत्र की तरह ही व्यवहार करने को मजबूर कर सकता है।

स्वामी, प्रकाशक वं मुद्रक विजय कुमार ने अशोक सम्राट प्रिन्टर्स, 215, पीरागढ़ी गांव, दिल्ली-87 से मुद्रित कर बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086 प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार। (RNI No. 70098/99) इस समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी हैं। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगें। Phone : 9810674206

संजय दत्त के क्लब में बजने वाले गानों पर विवाद : बिना इजाजत बज रहे कॉपीराइट वाले गाने, शिकायत मिलने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई रोक

पुणे में एक्टर संजय दत्त के नाइटक्लब क्ख्द्यद्यह्ल पर कॉपीराइट विवाद खड़ा हो गया है। क्लब में बिना इजाजत कॉपीराइट वाले गाने बजाए जा रहे थे। फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में शिकायत की कि क्लब में बिना लाइसेंस कॉपीराइट म्यूजिक का इस्तेमाल हो रहा है। कोर्ट ने पीपीएल को अंतरिम राहत देते हुए Ballr को जरूरी लाइसेंस के बिना अपने कलेक्शन की साउंड रिकॉर्डिंग सार्वजनिक रूप से बजाने से रोक दिया। पीपीएल के एक प्रतिनिधि ने 24 जून को Ballr का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने क्लब में पीपीएल के कलेक्शन के कई कॉपीराइट वाले गाने बजते हुए पाए। Ballr के मालिक एक्टर संजय दत्त और हेरंब शेलके हैं। इन गानों में 'बदतमीज दिल', 'मौजा ही मौजा', 'दर्द-ए-डिस्को', 'ओ साकी साकी' और 'दस बहाने' शामिल हैं। क्लब में बजाए जा रहे गानों की लिस्ट में इंटरनेशनल सॉन्ग भी शामिल थे। इनमें जस्टिन बीबर का 'व्हाट डू यू मीन' और दुआ लिपा का 'लेविटेटिंग' शामिल है। पीपीएल का दावा है कि इन सभी साउंड रिकॉर्डिंग का कॉपीराइट उसी संस्था के पास है। 7 अगस्त के आदेश में बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाइटक्लब के मालिकों को जरूरी नॉन-एक्सक्लूसिव पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस के बिना पीपीएल के कलेक्शन की साउंड रिकॉर्डिंग बजाने या इस्तेमाल करने से रोक दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि क्ख्द्यद्यह्ल ने पहले पीपीएल

इंडिया से उसके कलेक्शन का म्यूजिक इस्तेमाल करने के लिए कॉपीराइट लाइसेंस लिया था। पीपीएल इंडिया कॉपीराइट वाली साउंड रिकॉर्डिंग के लाइसेंस का काम देखती है। हालांकि, यह लाइसेंस एक्सपायर हो गया था और इसे रिन्यू नहीं कराया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने पीपीएल को अंतरिम राहत दी और Ballr में बिना जरूरी इजाजत कॉपीराइट वाली रिकॉर्डिंग इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया। पीपीएल का कहना है कि मनोरंजन के लिए कॉपीराइट म्यूजिक बजाने वाले कमर्शियल संस्थानों को जरूरी लाइसेंस लेना होगा। संस्था उन जगहों पर भी नजर रख रही है, जहां बिना इजाजत उसकी रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल हो सकता है। आदेश के बाद पीपीएल के वकील हितेन वासन ने कहा कि संस्था उन मामलों की पहचान करना जारी रखेगी, जहां बिना जरूरी मंजूरी कॉपीराइट वाले संगीत का इस्तेमाल किया जा रहा है। वासन ने कहा, 'बॉम्बे हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश साफ मैसेज देता है कि कॉपीराइट वाले संगीत का बिना मंजूरी लगातार इस्तेमाल करने पर गंभीर कानूनी नतीजे हो सकते हैं। 'कोर्ट का आदेश इस मामले में अंतरिम कदम है। यह विवाद से जुड़े सभी मुद्दों पर अंतिम फैसला नहीं है। फिलहाल, Ballr को जरूरी लाइसेंस लिए बिना पीपीएल के कलेक्शन की रिकॉर्डिंग इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। पीपीएल की शिकायत के बाद कमर्शियल जगहों पर म्यूजिक लाइसेंस के मुद्दे पर फिर ध्यान गया है। कमर्शियल जगहों को अपने मेहमानों के लिए कॉपीराइट वाले गाने बजाने से पहले जरूरी मंजूरी लेनी होती है।

बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहा है

गोविंदा पर भड़कीं पत्नी सुनीता आहूजा; शर्म आनी चाहिए, शुगर डैडी बन गया

अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अपने पति पर तीखा हमला बोला है। सुनीता ने गोविंदा के एक्ट्रेस कोमल रॉय के साथ एयरपोर्ट पर दिखने पर कड़ी नाराजगी जताई। सुनीता ने कहा कि गोविंदा को बेटी की उम्र की लड़की के साथ इस तरह घूमने पर थोड़ी शर्म आनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कोमल के कपड़ों पर भी तंज कसा। सुनीता ने कहा कि बिना फिल्म बने कोई प्रमोशन नहीं होता, यह सब घटिया सोच को दिखाता है। सुनीता से गोविंदा के कोमल रॉय के साथ दोबारा नजर आने पर सवाल पूछा, तो उन्होंने कड़े शब्दों में जवाब दिया। सुनीता ने कहा कि फिल्म बनने के बाद ही उसका प्रमोशन किया जाता है, बिना किसी फिल्म के यह सब करने का क्या मतलब है। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि गोविंदा अपनी बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूम रहे हैं और उन्हें इस बात पर थोड़ी शर्म आनी चाहिए। सुनीता आहूजा ने

केवल गोविंदा ही नहीं, बल्कि उनके साथ दिख रही कोमल के ड्रेसिंग सेंस पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर सामने वाले का शुगर डैडी इतना अमीर है, तो कम से कम कपड़े तो ढंग के पहनने चाहिए। इंसान का अपना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। सुनीता ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि लोगों को देखना चाहिए कि वे किस तरह स्टाइल के साथ रहते हैं। उन्होंने पूरे वाकये को बहुत खराब और घटिया सोच करार दिया।

गोविंदा हाल ही में एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ एयरपोर्ट पर दूसरी बार स्पॉट हुए थे। बता दें कि सुनीता ने कुछ समय पहले ही कहा था कि उन्हें कोमल नाम से नफरत है।

गोविंदा को एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ 7 अगस्त को एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट किया गया था। सुनीता ने मिस मालिनी को दिए इंटरव्यू में गोविंदा के अफेयर रूमर्स पर बात करते हुए कहा था कि जवानी में गलतियां होती हैं, लेकिन 63 की उम्र में ये सब सुनना ठीक नहीं है। करियर के चलते गोविंदा ने सुनीता से शादी को लगभग दो साल तक दुनिया से छिपाकर रखा था। सुनीता ने कहा था, 'ये नाम थोड़ा गड़बड़ है। मुझे कोमल नाम से नफरत है। एक है कोमल, एक्स वाय जेड है कोई। मुझे उससे नफरत है।' गोविंदा 7 साल बाद बॉलीवुड कमबैक कर रहे हैं और अपने प्रोडक्शन की इस फिल्म से कोमल को भी लॉन्च कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कोमल के गोविंदा की दूसरी फिल्म दुनियादारी में होने की भी खबरें हैं। गोविंदा ने जुलाई में अपकमिंग फिल्म रूपा से जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोमल का मीडिया से परिचय करवाया और तारीफ कर कहा कि फिल्म देखने के बाद दर्शक उन्हें अच्छी एक्ट्रेस मानेंगे। गोविंदा ने हाल ही में सुनीता के उन आरोपों पर जवाब दिया, जिनमें उन्होंने उनके अफेयर्स की बात कही थी।

यूजर ने वामिका गब्बी को क्यों कहा बॉलीवुड का शाहिद अफरीदी? 'आवारापन 2' के इवेंट में हुई ट्रोल

वामिका गब्बी 'आवारापन 2' इवेंट में एक खास फैशन स्टेटमेंट बनाने के इरादे से पहुंचीं। इवेंट में सबकी नजरें उन पर टिक गईं। यहां अभिनेत्री स्पोर्टी स्ट्रीटवियर में नजर आईं। उनके इस एक्सपेरिमेंटल लुक ने ऑनलाइन चर्चा छेड़ दी। सोशल मीडिया यूजर्स उनकी इस अनोखी स्टाइलिंग को लेकर बंटे हुए दिखे। इवेंट के लिए वामिका ने आम ग्लैमरस रेड-कारपेट ड्रेस के बजाय कुछ अलग ही पहना। उन्होंने भूरे और काले रंग की एक ओवरसाइज्ड लेपर्ड-प्रिंट फुटबॉल जर्सी पहनी, जिससे उनका लुक अलग ही लगा। जर्सी में काले और सफेद रंग का कॉन्ट्रास्टिंग कॉलर था। वामिका ने इस ओवरसाइज्ड जर्सी को मिनी ड्रेस की तरह पहना। जहां वामिका ने एक एक्सपेरिमेंटल फैशन लुक अपनाया, वहीं इंटरनेट पर लोगों की राय बंटी हुई थी। कई यूजर्स ने खुलकर उनकी स्टाइलिंग की आलोचना की, खासकर ओवरसाइज्ड जर्सी, अनोखे चश्मे और छोटे बालों के कॉम्बिनेशन की। एक यूजर ने मजाक में उन्हें 'बॉलीवुड का शाहिद अफरीदी' कहा, तो दूसरे ने बस इतना पूछा, 'ये क्या है?' कुछ कमेंट्स तो काफी कड़े थे, जैसे 'बकवास', 'छपरी' और 'जोकर लग रही है...' हालांकि, हर कोई उनके लुक से नाखुश नहीं था। फैंस का एक ग्रुप वामिका के बचाव में आगे आया। उन्होंने इस लुक को 'शानदार' बताया। वामिका गब्बी हाल ही में फिल्म 'डीसी' में नजर आई हैं। यह फिल्म अच्छा कलेक्शन कर रही है। उनके पास कई फिल्में हैं, जिनमें 'प्रहार', 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' और 'कुकु की कुंडली' शामिल हैं।

रानी मुखर्जी को मिला खास सम्मान, सिनेमा में पूरे किए 3 दशक, बोलीं- 'मेरी फिल्में और किरदार...'

रानी मुखर्जी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक अलग-अलग किरदार निभाए हैं। उन्होंने कभी समाज की सोच को चुनौती देने वाली महिलाओं का किरदार निभाया, तो कभी मुश्किल हालात में हिम्मत दिखाने वाली महिलाओं की कहानी पर्दे पर उतारी। अब इसी को देखते हुए उन्हें विशेष सम्मान दिया गया है। तीन दशक से ज्यादा समय से अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाली रानी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (ढ्ढस्नस्नरू) में खास सम्मान दिया गया है। उन्हें एक्टिंग में बेहतरीन योगदान के लिए स्पेशल सिटेशन से सम्मानित किया गया। रानी के इस सम्मान को भारतीय सिनेमा में उनके लंबे और शानदार सफर के लिए एक बड़ी पहचान माना जा रहा है। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे किरदार निभाए हैं, जिन्हें आज भी दर्शक याद करते हैं। उनके किरदारों और फिल्मों ने भारत के साथ-साथ विदेशों में भी लोगों के दिलों तक जगह बनाई है। 'ब्लैक', 'हम तुम', 'युवा', 'बंटी और बबली', 'नो वन किल्ड जेसिका', 'हिचकी', 'मर्दानी' फ्रेंचाइजी और 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' जैसी फिल्मों में रानी की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया है। रानी ने हर फिल्म में अपने किरदार को पूरी ईमानदारी और भावनाओं के साथ निभाने की कोशिश की है। यही वजह है कि उनके कई किरदार आज भी दर्शकों के बीच खास जगह रखते हैं। इस सम्मान के बाद रानी मुखर्जी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी फिल्में, उनके किरदार और उनकी आवाज घर से बहुत दूर तक पहुंची हैं। उनके लिए यह सफर बेहद खास रहा है। रानी का यह सम्मान सिर्फ उनकी एक्टिंग को पहचान नहीं देता, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारतीय सिनेमा की कहानियां अब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में दर्शकों तक पहुंच रही हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 का आयोजन 13 से 23 अगस्त तक किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में भारत के अलग-अलग हिस्सों से फिल्में, कलाकार और फिल्ममेकर शामिल हो रहे हैं।

सनी देओल बोले- 'मैं दुनिया का पापा हूं':'ऑगी एंड द कॉकरोचेज' कार्टून का डायलॉग सुनाया; बंटवारा 1947 के प्रमोशन में पहुंचे थे

अभिनेता सनी देओल अपनी नई फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के सिलसिले में कोलकाता पहुंचे थे। फिल्म की स्टारकास्ट और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ आयोजित एक कार्यक्रम में सनी ने फैंस से सीधी बातचीत की। इस दौरान एक फैन के कहने पर उन्होंने मशहूर एनिमेटेड शो 'ऑगी एंड द कॉकरोचेज' का एक डायलॉग अपनी आवाज में बोलकर सुनाया। हिंदी में डब हुए इस कार्टून शो में जैक नाम के किरदार की आवाज सनी देओल की मिमिक्री स्टाइल में रखी गई है। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोलकाता के ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम के दौरान एक फैन ने सनी देओल से कार्टून शो से जुड़ा एक डायलॉग बोलने का निवेदन किया। फैन ने एक्टर को बताया कि 'ऑगी एंड द कॉकरोचेज' शो में उनकी आवाज जैसी डबिंग में एक लाइन है, 'ओये मैं पापा हूं, दुनिया का

पापा'। सनी देओल ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने यह शो कभी नहीं देखा है, लेकिन वे कोशिश करते हैं। इसके बाद सनी ने अपने सिग्नेचर पंजाबी और हिंदी अंदाज में जोर से यह डायलॉग बोला, जिसे सुनकर पूरे हॉल में मौजूद फैंस ने जमकर तालियां बजाईं। 'ऑगी एंड द कॉकरोचेज' मूल रूप से कनाडा का एक लोकप्रिय एनिमेटेड शो है, जिसे जीन-इवेस रायमबॉड ने बनाया था। 1998 से 2019 के बीच इसके 7 सीजन प्रसारित हुए थे। भारत में यह शो साल 2009 में निकलोडियन चैनल पर पहली बार दिखाया गया था। इसके बाद 2012 में जब यह कार्टून नेटवर्क पर आया, तो इसके किरदारों को बॉलीवुड स्टार्स की मिमिक्री आवाज में डब किया गया। इसमें जैक नाम की हरी बिल्ली के किरदार की आवाज सनी देओल की स्टाइल में रखी गई थी, जो भारत के बच्चों और युवाओं के बीच काफी मशहूर हुई थी। सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सनी देओल एक मुस्लिम व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं, जो देश के विभाजन के समय पाकिस्तान चला जाता है। वहां उसे अपने नए घर में एक हिंदू महिला मिलती है, जिसका किरदार शबाना आजमी ने निभाया है। फिल्म की कहानी में सनी उस महिला और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते नजर आते हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म में प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह और कनिष्का कपूर ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं।

नेशनल मीडिया कॉन्क्लेव में मनोज कुमार शर्मा को मास कम्युनिकेशन में ऑनरेरी डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया

नई दिल्ली। (ए,के,चौधरी) पीआर गुरु के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक मनोज कुमार शर्मा को अमेरिकन ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी द्वारा नई दिल्ली के द ललित, कनॉट प्लेस में आयोजित समारोह में मास कम्युनिकेशन में ऑनरेरी डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। यह सम्मान संचार, शिक्षा, जनसंपर्क और मीडिया के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव एवं योगदान को मान्यता प्रदान करता है। मनोज कुमार शर्मा ने 2018 में पीआर गुरु की स्थापना की और वर्तमान में इसके संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक के रूप में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में पीआर गुरु विभिन्न क्षेत्रों के संस्थानों और कंपनियों को जनसंपर्क, रणनीतिक संचार और मीडिया आउटरीच जैसी सेवाएं प्रदान कर रहा है। पीआर गुरु से पहले उन्होंने गोल्डमाइन एडवरटाइजिंग में डायरेक्टर, पीआर के रूप में कार्य किया। साथ ही, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में कंसल्टेंट (डिप्टी डायरेक्टर) के रूप में भी सेवाएं दीं, जहां वे संचार शिक्षा, पाठ्यक्रम एवं नए कोर्स तैयार करने से जुड़े रहे। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

उन्होंने आईआईएलएम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, विगन एंड लेह कॉलेज, एनबीए ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और महाराजा अग्रसेन कॉलेज में विभिन्न शैक्षणिक एवं नेतृत्वकारी पदों पर कार्य किया।

मनोज कुमार शर्मा ने सम्मान पर कहा, ऑनरेरी डॉक्टरेट मेरे संचार और शिक्षा के सफर की महत्वपूर्ण पहचान है। सीखना मेरे लिए हमेशा निरंतर प्रक्रिया रही है और यह सम्मान मुझे आगे भी योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। मीडिया एवं सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें प्राइड ऑफ इंडिया और भारत श्री जैसे सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। अमेरिकन ईस्ट कोस्ट यूनिवर्सिटी ने उनकी उपलब्धियों, मानवता के प्रति सेवाओं तथा राष्ट्र के विकास में योगदान को देखते हुए उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया।

विदेश नीति का मतलब सिर्फ नेताओं को गले लगाना है - राहुल गांधी

नई दिल्ली । दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर लोगों को अपनी बात रखने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रही उत्तराखंड की एक महिला का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि सरकार व्यवस्था लागू करना चाहती है, जबकि कांग्रेस का काम भारत को अपनी बात कहने का अवसर देना है। राहुल गांधी ने कहा कि जंतर-मंतर पर छात्र अपनी बात रखना चाहते थे। उनके मुताबिक, छात्र परेशान थे और अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि जंतर-मंतर पर व्यवस्था बनाई जाएगी और लोगों को अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देने के दौरान एक पुलिसकर्मी ने उनसे सरकार के लोगों को हटाने की बात कही थी। राहुल ने यह भी कहा कि कुछ मीडिया कर्मी निजी तौर पर मानते हैं कि जो हो रहा है, वह सही नहीं है, लेकिन नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण खुलकर बोल नहीं पाते। राहुल गांधी ने कहा कि देश में एक राष्ट्रीय भावना भी होती है। उनके मुताबिक, इसका मतलब यह है कि लोग कुछ लोगों को अपनी बनाई हुई व्यवस्था देश पर थोपने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष अब अपनी बात खुलकर रख रहा है और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने एक महिला का जिक्र करते हुए कहा कि वह कार्यक्रम में उनसे मिली थीं। उन्होंने बताया कि महिला की बेटी के साथ चार साल पहले उत्तराखंड में दुष्कर्म हुआ और उसकी हत्या

कर दी गई थी।

राहुल के अनुसार, महिला रो रही थी और अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन व्यवस्था की ओर से उसे भी अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार और उसकी राजनीतिक विचारधारा भारत पर एक ऐसी व्यवस्था थोपना चाहती है, जो सरकार और कुछ अन्य लोगों के हित में हो। उन्होंने कहा कि सरकार का काम देश में एक व्यवस्था लागू करना है, जबकि उनका काम भारत को अपनी बात रखने का अवसर देना और उस व्यवस्था को तोड़ना है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि उनका काम बेहद आसान है और उनकी कोशिशें सरकार को परेशान कर सकती हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात में सो नहीं पाते। राहुल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें कभी चाणक्य और सरदार पटेल जैसे नामों से जोड़ा जाता था, लेकिन अब वह संसद भवन में प्रवेश तक नहीं कर पाए। राहुल ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार उन्हें भारत की आवाज और उसकी अभिव्यक्ति का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीडिया से संवाद को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या कभी प्रधानमंत्री को इस तरह बातचीत करते देखा गया है और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। राहुल ने कहा कि पहले उन्हें लगता था कि प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी एक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री के साथ पांच मिनट कमरे में रहने के बाद उन्हें लगा कि वह मीडिया का सामना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा नहीं देते, तब तक विपक्ष उन्हें चैन से नहीं बैठने देगा।

राहुल ने यह भी दावा किया कि उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर से जानकारी मिलती है और वहां अंदरूनी असंतोष है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहा हो और डर महसूस करे तो इसे समझा जा सकता है, लेकिन यहां तो ऐसे लोगों से मुकाबला है जिन्हें वे जोकर और क्लाउन कहते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस से जुड़े लोगों को भारत के दर्शन और इतिहास की समझ नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को समझने के लिए केवल 3,000 साल पुराने इतिहास को जानना पर्याप्त नहीं है। भारत को समझने के लिए उसे आज, इसी समय और उसकी वर्तमान अभिव्यक्ति के जरिए समझना जरूरी है। पहले आरएसएस से जुड़े छोटे कारोबारी, मिठाई विक्रेता, सोनार, लोहार और बनिया समुदाय के लोग संगठन का हिस्सा थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाया गया और उनके साथ धोखा हुआ। उन्होंने कहा कि तस्ञ और नोटबंदी जैसी नीतियों का असर इन छोटे कारोबारियों पर पड़ा। राहुल ने दावा किया कि ऋस्र में पूंजी का प्रवेश प्रमोद महाजन के दौर में शुरू हुआ और अब नरेंद्र मोदी के समय में इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।

दिल्ली में ब्रिटानिया चौक फ्लाईओवर से गिरकर महिला की मौत, घटना की जांच में जुटी पुलिस

पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में पंजाबी बाग इलाके में ब्रिटानिया चौक के पास फ्लाईओवर से गिरकर 29 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को उपचार के लिए आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल, मोती नगर ले जाया गया। हालत गंभीर होने के कारण बाद में उसे आरएमएल अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, पंजाबी बाग थाना पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी कि ब्रिटानिया चौक के पास फ्लाईओवर से एक महिला गिर गई है। सूचना मिलते ही जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे। तब तक राहगीर महिला को आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल ले जा चुके थे। अस्पताल पहुंचने पर महिला की हालत गंभीर थी और वह बोलने की स्थिति में नहीं थी।

अशोका एक्सप्रेस

अशोका एक्सप्रेस की बेवसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करे।

अशोका एक्सप्रेस
राष्ट्रीय हिन्दी समाचार-पत्र

प्रिय पाठक, विज्ञापन दात्ता,
आप अपने क्षेत्र की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य तथा धार्मिक लेख, कविता एवं कार्टून लिख भेजें। व्हाट्सएप या ईमेल पर आपके द्वारा भेजी गई सामग्री सुव्यवस्थित ढंग से प्रकाशित किया जायेगा।
नोट: पूर्व प्रकाशित लेखो को न भेजे।
संपादक: विजय कुमार
Website: https://ashokaexpress.com/, Email:-ashoka.express@live.com, Mobile No. 9810674206

अशोका एक्सप्रेस को आर्थिक योगदान भी कर सकते है।

Account Holder Name : ASHOKA EXPRESS
Bank Account No. : 10650995502 & 41856402452
IFSC Code : SBIN0004846
UPI ID : 9810674206@sbi

'भारत की सहनशीलता को न समझें' डोभाल ने दिलाई ऑपरेशन सिंदूर की याद

नई दिल्ली ।राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत की उदारता और सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझना बड़ी भूल होगी. उन्होंने कहा कि भारत जरूरत पड़ने पर जोखिम उठाने और बिना परिणाम की चिंता किए कड़ा जवाब देने की क्षमता रखता है. डोभाल ने ये बातें डिस्कवरी की आने वाली डॉक्यूसीरीज डीक्लासिफाइडः ऑपरेशन सिंदूर में कहीं. यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला इंटरव्यू बताया जा रहा है. डोभाल के मुताबिक, 88 घंटे चले सैन्य अभियान का मुख्य लक्ष्य दुश्मन के आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था. खास तौर पर उन ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिन्हें पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ा गया था. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि भारत शांति और सहनशीलता में विश्वास करता है, लेकिन इसे कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए. डिस्कवरी के अनुसार, दो हिस्सों वाली इस डॉक्यूसीरीज में भारत के सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव दिखाए जाएंगे. इसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लिए गए फैसलों और सरकार की प्रतिक्रिया से जुड़े पहलुओं पर भी जानकारी दी जाएगी. डोभाल डॉक्यूसीरीज में सैन्य कार्रवाई के पीछे की सोच और फैसले लेने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे. डीक्लासिफाइडः ऑपरेशन सिंदूर का प्रीमियर शनिवार को रात 9 बजे डिस्कवरी और डिस्कवरी+ पर होने की जानकारी दी गई है. ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू किया गया था. इससे पहले 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी. इसके बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी. अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के प्रमुख अधिकारियों में शामिल हैं. वह भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. उन्हें 30 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था. एनएसए के रूप में अजीत डोभाल प्रधानमंत्री को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, आतंकवाद, खुफिया मामलों और रणनीतिक चुनौतियों से जुड़े मुद्दों पर सलाह देते हैं. भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में उनकी भूमिका चर्चा में रही है. डोभाल ने अपने करियर का लंबा समय खुफिया और सुरक्षा से जुड़े कामों में बिताया. इस अनुभव के कारण उन्हें भारत की सुरक्षा और रणनीतिक नीति से जुड़े प्रमुख चेहरों में गिना जाता है. उनका अनुभव खास तौर पर आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जाता है.

बेचैनी की शिकायत के बाद जेपी नड्डा की एम्स दिल्ली में हुई कोरोनरी एंजियोग्राफी

नई दिल्ली।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी के लिए नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रखा गया है। अस्पताल ने शुक्रवार को बताया कि बेचैनी की शिकायत के बाद उनकी मेडिकल जांच की गई थी।

14 अगस्त के एक आधिकारिक बयान में,एम्स नई दिल्ली ने कहा कि 13 अगस्त की शाम को नड्डा की बेचैनी के लिए जांच की गई थी। मेडिकल जांच के हिस्से के तौर पर, उनके कई टेस्ट किए गए, जिनमें कोरोनरी एंजियोग्राफी भी शामिल थी। एम्स ने डॉ. (प्रो.) रीमा दादा के हस्ताक्षर वाली प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा की 13 अगस्त 2026 की शाम को बेचैनी के लिए जांच की गई, जिसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट शामिल थे।

वे अभी स्थिर हैं और कार्डियोलॉजी विभाग में निगरानी के लिए भर्ती हैं।' बयान में उनकी बेचैनी की वजह या एंजियोग्राफी के नतीजों के बारे में और जानकारी नहीं दी गई। गुरुवार शाम बेचैनी महसूस

होने के बाद नड्डा को एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के अनुसार, डॉक्टरों ने उनकी मेडिकल जांच की, जिसमें कोरोनरी एंजियोग्राफी भी शामिल थी। एम्स ने कहा कि नड्डा की हालत अभी स्थिर है और उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग में निगरानी में रखा गया है।

अस्पताल ने एंजियोग्राफी के नतीजों के बारे में और जानकारी या कोई खास बीमारी का पता चलने की बात नहीं बताई है। नड्डा केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के साथ-साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। वे हाल के हफ्तों में काफी सक्रिय रहे हैं, बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं और देश भर में स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचे से जुड़ी पहलों की समीक्षा कर रहे हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी दिल की बीमारियों का पता लगाने वाला एक टेस्ट है, जिसका इस्तेमाल दिल तक खून पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाओं की जांच के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान, डॉक्टर एक पतली कैथेटर के ज़रिए कोरोनरी धमनियों में एक खास कंट्रास्ट डाई डालते हैं; यह कैथेटर आमतौर पर कलाई या जांघ की धमनी के ज़रिए डाला जाता है। इसके बाद एक्स-रे इमेजिंग से डॉक्टर यह देख पाते हैं कि धमनियां सिकुड़ गई हैं या उनमें रुकावट है। यह टेस्ट डॉक्टरों को कोरोनरी धमनी की संभावित बीमारी का पता लगाने और यह तय करने में मदद कर सकता है कि क्या आगे इलाज (जैसे दवाएं, एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग) की ज़रूरत है।

अरुणाचल में चाइना की घुसपैठ चिंताजनक! खड़गे और राहुल ने मोदी सरकार से माँगा जवाब

नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 14 अगस्त को उन खबरों पर चिंता जताई कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को रोक दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए स्थिति को 'बेहद चिंताजनक' बताया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। गांधी ने आरोप लगाया कि चीन के खिलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय, मोदी सरकार इस मुद्दे पर मीडिया कवरेज को दबाने की कोशिश कर रही है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर हमारी सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है - यह बेहद चिंताजनक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी है। चीन को रोकने के बजाय, मोदी सरकार इस खबर को दबाने के लिए मीडिया पर

दबाव डाल रही है। उन्होंने गलवान झड़प के बाद प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का भी ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की कोई ज़मीन नहीं कब्ज़ाई है; गांधी का कहना था कि इस बयान से देश को नुकसान पहुँचा है। गांधी ने आगे कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान देने के बजाय प्रधानमंत्री की छवि बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। पोस्ट में लिखा था कि देश को आज भी गलवान के बाद प्रधानमंत्री का वह बयान याद है, जिसमें उन्होंने यह कहकर भारत को भारी नुकसान पहुँचाया कि चीन ने हमारी ज़मीन का एक इंच भी हिस्सा नहीं लिया है।

आज भी उनकी छवि बचाने का वही काम जारी है - और जो प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा से ज़्यादा अपनी झूठी छवि को अहमियत देता है, वह देश के लिए बेहद खतरनाक है। इसके अलावा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी गतिविधियों में कथित बढ़ोतरी पर चिंता जताई। उन्होंने भारतीय सेना की पेट्रोलिंग और सीमावर्ती इलाकों तक पहुँच में कथित बदलावों को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किए। खड़गे ने पूछा कि क्या पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने टक्सिंग के पास अपनी मौजूदगी बढ़ाई है और क्या भारत की पहुँच शेरा-5 (एक तय पेट्रोलिंग पॉइंट) तक नियमित रूप से नहीं रही है।

एक्स पर लिखते हुए खड़गे ने कहा कि गलवान के बाद अब अरुणाचल प्रदेश? चिंताजनक खबरें बताती हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में और अंदर आने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे देश का अभिन्न अंग है। इस पर मोदी सरकार से तुरंत जवाब की मांग है।

क्या पीएलए ने टक्सिंग के पास अपनी मौजूदगी बढ़ाई है और क्या भारत की शेरा-5 (जो एक तय पेट्रोलिंग पॉइंट है) तक नियमित पहुंच खत्म हो गई है? इस संवेदनशील इलाके में सर्दियों के दौरान भारतीय पेट्रोलिंग सीमित क्यों रहती है, जबकि पीएलए पूरे साल वहां मौजूद रहती है? स्थानीय समुदायों के लिए पारंपरिक चरागाह और शिकार के इलाके क्यों पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं?

कांग्रेस ने जाति जनगणना पर केंद्र को घेरा, जयराम रमेश बोले- मंशा संदेहास्पद

नई दिल्ली । कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे पर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जातियों की सूची उपलब्ध नहीं कराए जाने और उत्तरदाताओं द्वारा बताए गए जवाब को उसी रूप में दर्ज किए जाने की व्यवस्था से सरकार की मंशा पर गंभीर संदेह पैदा होता है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में राजनीतिक दलों के साथ कोई चर्चा नहीं की गई। उनका कहना था कि यह उम्मीद की जा रही थी कि जाति संबंधी सवाल बिहार और तेलंगाना में किए गए जाति सर्वेक्षणों की तरह राज्यवार पहले से तैयार सूची के साथ पूछा जाएगा और उत्तर के अनुरूप उचित विकल्प पर केवल निशान लगाया जाएगा। रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ है, जिससे मंशा पर गंभीर संदेह पैदा होता है।'' उन्होंने 'एक्स' पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा 5 मई, 2025 को जाति जनगणना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र को भी साझा किया। रमेश ने कहा, ''यह पांच मई, 2025 को जाति जनगणना के संबंध में प्रधानमंत्री को लिखा गया कांग्रेस अध्यक्ष का पत्र था। उनके सबसे पहले और बुनियादी सुझाव को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। साथ ही, खरगे जी की मांग के अनुसार राजनीतिक दलों के साथ भी कोई चर्चा नहीं की गई है।'' केंद्र ने शुक्रवार को जनसंख्या गणना के चरण के तहत उत्तरदाताओं से पूछे जाने वाले 40 सवालों को अधिसूचित किया। इनमें जाति और कोविड टीकाकरण की जगह से संबंधित सवाल भी शामिल हैं। इस महीने की शुरुआत में जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फ से ढके क्षेत्रों में जनसंख्या गणना एक से 30 सितंबर तक होगी। इसमें कहा गया है, ''उपरोक्त जनगणना के संचालन के लिए घर-घर जनसंख्या गणना शुरू होने से ठीक पहले 17 से 31 अगस्त तक स्व-गणना का विकल्प उपलब्ध होगा।'' देश के बाकी हिस्सों में जनसंख्या गणना अगले साल शुरू होगी। यह पहली बार होगा जब जनगणना के तहत जाति संबंधी विवरण एकत्र किए जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रश्नावली में जातियों की सूची दिए जाने की संभावना नहीं है और उत्तरदाताओं द्वारा बताए गए जवाब को उसी रूप में दर्ज किया जाएगा। जाति जनगणना का निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पिछले साल 30 अप्रैल को लिया था।

हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद पर सीएम धामी का पलटवार, कांग्रेस पर विक्टिम कार्ड खेलने का लगाया आरोप

देहरादून । कांग्रेस ने गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद रैली स्थल के 'शुद्धिकरण' की निंदा की और आरोप लगाया कि यह घटना भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 'दलित-विरोधी' मानसिकता को दर्शाती है। इसको लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि खड़गे जी एक बहुत सम्मानित राष्ट्रीय नेता हैं। उनके अपमान के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। धार्मिक भावनाएं आहत होने पर कुछ संगठनों ने वहां विरोध किया था; कांग्रेस पार्टी ने इसे दलित मुद्दा बनाने की कोशिश की। धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग इसे अच्छी तरह देख सकते हैं। देश भी यह देख रहा है। बीजेपी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था... इसे ऐसा रंग देना दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह सत्ता चाहती है। वे विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। पूरा देश जानता है कि उन्होंने बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी और डॉ. भीमराव अंबेडकर के साथ क्या किया था। इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने भी सदन में यह मुद्दा उठाया और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ 'अस्पृश्यता निवारण अधिनियम' के तहत मामला दर्ज

करने की मांग की। वहीं, चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने इस घटना की निंदा की। खड़गे ने पूछा कि क्या लोकतंत्र ऐसे ही काम करता है? आप संविधान की रक्षा कैसे कर रहे हैं? उन्होंने यह भी कहा कि उनका मकसद इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना नहीं है, लेकिन मंच को शुद्ध करके उन्होंने उनका 'अपमान' किया है।

नड्डा ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है। हम इसकी जांच करेंगे और मैं इस घटना की निंदा करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जनसभा के बाद मंच का 'शुद्धिकरण' करना 'सिर्फ़ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि यह उस संविधान का अपमान है जिसने छुआछूत को अपराध घोषित किया था'। उन्होंने 'एक्स' पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, 'और यह कोई अकेली घटना नहीं है। यह बीजेपी-आरएसएस द्वारा बरसों से पाले-पोसे गए मनुवादी सोच का नतीजा है - वह घिनौनी सोच जो आज भी इंसान का दर्जा उसकी बराबरी और इंसानियत से नहीं, बल्कि उसके जन्म से तय करती है।' एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, उत्तराखंड के लिए कांग्रेस की प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा ने स्वदूक दर्ज करने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की मांग की।

हरभजन सिंह का दावा, वैभव सूर्यवंशी पर आक्रामक गेंदबाजी ही एकमात्र तरीका

भारत के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी का बेखौफ आक्रामक बल्लेबाजी प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बेजोड़ है और इस 15 वर्षीय बल्लेबाज को रोकने के लिए किसी भी गेंदबाज को आक्रामक रुख अपनाना होगा क्योंकि उसे बांधकर रखना कोई विकल्प नहीं है। हरभजन का मानना है कि कम उम्र और सीमित अनुभव के बावजूद सूर्यवंशी गेंदबाज के मन में संदेह पैदा करने की क्षमता रखते हैं। हरभजन ने पीटीआई को दिए पॉडकास्ट साक्षात्कार में कहा, ''वैभव सूर्यवंशी असाधारण हैं वह एक अलग तरह का खिलाड़ी है। मैंने इससे पहले ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा जो 14-15 साल की उम्र में ही दुनिया पर दबदबा बना सके।'' राजस्थान रॉयल्स की ओर से 2025 में 14 साल की उम्र में पदार्पण करने के साथ ही सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंद में शतक जड़कर पुरुष टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। उनका शानदार सफर इस साल भी जारी रहा और वह 15 साल 99 दिन की उम्र में ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ खेलकर भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। सूर्यवंशी ने अंडर-19 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंद में 175 रन की पारी खेली थी जो टूर्नामेंट के फाइनल के इतिहास का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और भारत ने खिताब अपने नाम किया। इस साल के आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के इस युवा बल्लेबाज ने दुनिया के शीर्ष तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और पैट कमिंस की पहली ही गेंदों पर छक्के लगाकर उनका शानदार अंदाज में स्वागत किया था। हरभजन ने कहा, ''जब दुनिया के शीर्ष गेंदबाज उसे गेंदबाजी कर रहे होते हैं तो वे असल में यह सोच रहे होते हैं कि गेंद कहां डालनी है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है।'' यह पूछे जाने पर कि ऐसे बल्लेबाज को कैसे गेंदबाजी की जाए जो गेंदबाज के नाम, मौके या क्षेत्ररक्षण से प्रभावित होने से इनकार करता हो, हरभजन ने कहा, 'बचे रहने का एकमात्र तरीका है कि उस पर आक्रमण करें। आप उस पर आक्रमण करें और उसका विकेट लें।'' उन्होंने कहा, ''यह हर बार काम नहीं करेगा। कई बार आप बुरी तरह पिट भी सकते हैं। वह छक्के लगा सकता है। लेकिन यह खेल का हिस्सा है। आपको स्वीकार करना होगा कि वह अच्छा खिलाड़ी है।'' पावरप्ले में सूर्यवंशी को गेंदबाजी करने की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर इस पूर्व भारतीय स्पिनर ने कहा, ''मैं उसके हिसाब से क्षेत्ररक्षण नहीं लगाऊंगा। मैं अपने हिसाब से क्षेत्ररक्षण लगाऊंगा।

गुरनूर और प्रसिद्ध में किसे मिलेगा मौका? गिल ने बताया; भारत के 600वें टेस्ट पर कही यह बात

गॉल । भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार से गॉल में खेला जाएगा। यह भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक मौका होगा, क्योंकि यह टीम इंडिया का 600वां टेस्ट मैच है। खास बात यह है कि मुकाबला भारत के स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस ऐतिहासिक मुकाबले से पहले कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि अपने देश के 600वें टेस्ट में कप्तानी करना उनके लिए बेहद खास अनुभव है। गिल ने कहा, 'अपने देश के 600वें टेस्ट में कप्तानी करना सम्मान की बात है और स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा करना इससे भी बड़ा सम्मान है।' गिल के लिए यह मुकाबला कप्तान के तौर पर भी अहम है। उन्होंने कहा कि अब वह अपनी भूमिका में सहज महसूस कर रहे हैं और टीम का सबसे बड़ा लक्ष्य विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में बने रहना है। भारत इस समय विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा चक्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रहा है। गिल ने साफ किया कि टीम को आगे लगातार जीत दर्ज करनी होगी। भारतीय कप्तान ने कहा, 'अब मैं कप्तान के तौर पर अपनी

भूमिका में सहज हूं। हमारा लक्ष्य विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में बने रहना है। इसके लिए हमें छह या सात टेस्ट जीतने होंगे। इसलिए हम यहां से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं।'

श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट भारत के लिए इसी अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। इसके बाद टीम को न्यूजीलैंड में दो मैचों की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज खेलनी हैं। फिर भारत को अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी भारत के लिए बड़ा झटका है। ऐसे में टीम के युवा और कम अनुभवी गेंदबाजों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी। गिल ने हालांकि इसे चुनौती के साथ-साथ दूसरे खिलाड़ियों के लिए मौका भी बताया। उन्होंने कहा, 'जसप्रीत बुमराह यहां नहीं हैं, लेकिन यह किसी और खिलाड़ी के लिए आगे आने का अवसर है। यह सब खेल की गति को समझने और उसके हिसाब से खेलने की बात है।' भारत को मोहम्मद सिराज के साथ दूसरे तेज गेंदबाज के चयन को लेकर भी माथापच्ची करनी है। गिल ने युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ की खूबियां बताईं, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के हालिया प्रदर्शन की भी तारीफ की। ऐसे में उन्होंने संकेत दिया कि दूसरे तेज गेंदबाज का चयन आसान नहीं होगा। गिल ने कहा, 'गुरनूर बराड़ शानदार हैं, क्योंकि वह अच्छी गति के साथ पुरानी गेंद से उछाल हासिल कर सकते हैं। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा भी हाल में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभ्यास मैच में देखा। इसलिए यह एक मुश्किल फैसला है।' गॉल की परिस्थितियों में भारत तीन स्पिनरों के साथ उतरता है या तेज गेंदबाजी को ज्यादा महत्व देता है, यह भी देखने वाली बात होगी। भारतीय टीम में कुछ नए चेहरों को मौका मिल रहा है। गिल ने कहा कि युवा खिलाड़ियों से तुरंत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद करने के बजाय उन्हें समय देना जरूरी है। उन्होंने कहा, 'खिलाड़ी अपने आप आगे बढ़ेंगे। हमें उन्हें समय देना होगा। कुछ खिलाड़ियों को थोड़ा समय चाहिए होता है।' साई सुदर्शन की चोट पर गिल ने बताया कि टीम प्रबंधन लगातार खिलाड़ियों के संपर्क में है। उन्होंने कहा, 'उनके साथ लगातार बातचीत होती रहती है। दुर्भाग्य से साई सुदर्शन उतना सुधार नहीं कर पाए, जितना हम चाहते थे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में हम जोखिम नहीं ले सकते। लेकिन हमें अपनी 15 खिलाड़ियों की टीम पर पूरा भरोसा है।'

एथलेटिक्स टीम में 72 खिलाड़ियों में 38 बेटियां; कॉमनवेल्थ गेम्स पदक विजेता यशवीर-सेल्वाप्रभु को नहीं मिली जगह

जापान के आयची और नगोया में 19 सितंबर से शुरू हो रहे एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट्स से काफी उम्मीदें हैं। हाल ही में हुए ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय दल एशियाड में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखना चाहेगा। हांगझोउ एशियाई खेलों में भारत के पदकों के शतकीय प्रदर्शन में सबसे बड़ा 29 पदकों का योगदान एथलेटिक्स का था। तब एथलेटिक्स में भारत को छह स्वर्ण, 14 रजत और नौ कांस्य समेत 29 पदक मिले थे। भारत ने पिछले एशियाड में कुल 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते थे और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। इस बार भी एथलेटिक्स में पिछले प्रदर्शन को और बेहतर करने की उम्मीद की जा रही है। इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) ने एशियाड के लिए पुरुषों के मुकाबले महिला एथलीटों पर ज्यादा भरोसा जताया है। जापान में कुल 72 भारतीय एथलीट शिरकत करने जा रहे हैं और इनमें 34 पुरुषों के मुकाबले 38 महिला एथलीटों की संख्या अधिक है।

एथलेटिक्स दल में राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता जेवलिन थ्रोअर यशवीर सिंह और ट्रिपल जंप में पदक जीतने वाले सेल्वाप्रभु टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। ट्रायल में इनसे बेहतर प्रदर्शन करने वालों को टीम में जगह दी गई है। वहीं, फॉर्म में नहीं चल रहीं पिछले एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अनुरानी को टीम में जगह दी गई है। हांगझोउ एशियाड, जो कि 2022 की जगह 2023 में आयोजित हुआ था, उसमें 35 पुरुष, 33 महिला एथलीटों समेत कुल 68 एथलीटों ने शिरकत की थी। इस बार चार एथलीट ज्यादा जा रहे हैं। पिछले एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा (जेवलिन थ्रो), अविनाश साबले (3000 मीटर स्टीपलचेज), तजिंदर पाल सिंह तूर (शॉटपुट), पारुल चौधरी (पांच हजार मीटर), अनुरानी (जेवलिन थ्रो) सभी टीम में हैं। इनके अलावा गुलवीर सिंह (पांच और 10 हजार) से उम्मीदें हैं। चार गुणा चार सौ मीटर रिले में राजेश रमेश, टीके विशाल, जय कुमार, मनु, धर्मवीर चौधरी, मोहम्मद अशफाक को रखा है। पुरुषों की चार गुणा सौ मीटर रिले टीम को नहीं उतारा जा रहा है। हालांकि लांग लिस्ट में रिले टीम का नाम था। उम्मीद की जा रही थी कि ग्लासगो में 85 मीटर से ऊपर भाला फेंककर कांस्य जीतने वाले यशवीर को टीम में जगह मिलेगी, लेकिन ट्रायल में 87 मीटर से ऊपर भाला फेंकने वाले रोहित यादव को वरीयता दी गई। एक इवेंट में दो एथलीट ही शिरकत कर सकते हैं। इस वजह से यशवीर शामिल नहीं हो पाए। शॉटपुट में ट्रायल में शीर्ष पर रहने वाले करनवीर को जगह मिली है। दूसरे एथलीट तूर हैं। समरदीप सिंह गिल टीम में जगह नहीं बना पाए। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल, कार्तिक उन्नीकृष्णन टीम में हैं। अनुरानी को पिछले एशियाड के प्रदर्शन के आधार पर टीम में जगह दी गई।

वीवीएस लक्ष्मण बनेंगे बसीसीआई के 'डायरेक्टर ऑफ़ क्रिकेट'? भारतीय क्रिकेट में होगा बड़ा फेरबदल!

भारत के पूर्व बल्लेबाज़ वीवीएस लक्ष्मण को बसीसीआई में एक बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि बोर्ड इस साल के आखिर में अपने क्रिकेट ऑपरेशन्स में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, बसीसीआई अहम पदों की व्यापक समीक्षा के तहत लक्ष्मण के लिए 'डायरेक्टर ऑफ़ क्रिकेट' का पद बनाने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीनियर पुरुष चयन समिति के चेयरमैन के तौर पर अजीत अगरकर का कार्यकाल, जो सितंबर में खत्म होने वाला है, उसे या तो जून 2027 तक बढ़ाया जा सकता है या फिर बोर्ड के भीतर चल रहे बड़े फेरबदल का हिस्सा बनाया जा सकता है। लक्ष्मण अभी बेंगलुरु में बसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के हेड के तौर पर काम कर रहे हैं, जहाँ वे अलग-अलग उम्र के खिलाड़ियों के लिए हाई-परफ़ॉर्मेंस प्रोग्राम, खिलाड़ियों के रिहैबिलिटेशन और टैलेंट डेवलपमेंट का काम देखते हैं। 'डायरेक्टर ऑफ़ क्रिकेट' बनने पर उन्हें शायद ज़्यादा बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रैटेजिक भूमिका मिल सकती है, जिससे सीनियर नेशनल टीम, सेलेक्टर, कोचिंग स्टाफ़ और सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस एक बेहतर तालमेल वाले स्ट्रक्चर के तहत जुड़ सकेंगे। हालांकि बसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन CoE के अलावा भारतीय क्रिकेट में लक्ष्मण की बढ़ती भागीदारी की वजह से ऐसी भूमिका की संभावना पर चर्चा हो रही है। जब भी सीनियर टीम का रेगुलर कोचिंग स्टाफ़ उपलब्ध नहीं रहा है, तब-तब लक्ष्मण ने अंतरिम हेड कोच की भूमिका निभाई है। हाल ही में, जब इंग्लैंड दौरे के बाद गौतम गंभीर और रेगुलर सपोर्ट स्टाफ़ को ब्रेक दिया गया था, तब लक्ष्मण ने युवा भारतीय टीम को ज़िम्बाब्वे में 3-0 से टी20 सीरीज़ जिताई थी।

तंजिद ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज

डार्विन ।ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच डार्विन में खेले जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश ने मजबूत पकड़ बना ली है। उसने ऑस्ट्रेलिया को 198 रन पर समेटने के बाद अच्छी खासी लीड ले ली है। इस लीड को बनाने में बांग्लादेश के लिए सबसे अहम भूमिका सलामी बल्लेबाज तंजिद हसन तमीम की रही। उन्होंने शुक्रवार को डार्विन टेस्ट के दूसरे दिन बेहतरीन शतक लगाया। इस शतक के साथ उन्होंने इतिहास भी रच दिया। अपने करियर का सिर्फ दूसरा टेस्ट खेल रहे 25 वर्षीय तंजिद ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए। तंजिद ने 190 गेंदों में आठ चौके और एक छक्के की मदद से 101 रन की शानदार पारी खेली। उन्होंने 2003 में केर्न्स में हनान सरकार के बनाए 76 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में किसी बांग्लादेशी बल्लेबाज का इससे पहले यही सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर था। तंजिद को पारी की शुरुआत में ही बड़ा जीवनदान मिला। दूसरी पारी के दूसरे ओवर में नाथन लियोन की गेंद पर वह शून्य के स्कोर पर कैच छूटने से बच गए। इसके बाद उन्होंने बेहद संयम के साथ बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण का सामना किया। उन्होंने मोमिनुल हक के साथ दूसरे विकेट के लिए 102 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। मोमिनुल 49 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने तंजिद का साथ दिया और बांग्लादेश की बढ़त को और मजबूत किया। तंजिद ने 188 गेंदों में चौका लगाकर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया। हालांकि, शतक पूरा करने के बाद वह ज्यादा देर नहीं टिक सके और नाथन लियोन की गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर कैच देकर 101 रन पर आउट हो गए। बांग्लादेश की मजबूत स्थिति की नींव तेज गेंदबाज हसन महमूद ने पहले दिन ही रख दी थी। उन्होंने 55 रन देकर छह विकेट चटकाए और ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को सिर्फ 198 रन पर समेटने में

अहम भूमिका निभाई। इसके बाद तंजिद ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़त की स्थिति में पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण में कप्तान पैट कमिंस के अलावा मिशेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन जैसे गेंदबाज मौजूद थे, लेकिन तंजिद ने धैर्य नहीं खोया। शतक के बाद तंजिद ने अपनी पारी को लेकर कहा, 'यह मेरे लिए बेहद खास है, क्योंकि मैं पहली बार यहां खेल रहा हूं। उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत अलग तरीके से गेंदबाजी की और मैं सामान्य क्रिकेट शॉट खेलने तथा खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। मैं जरूरत से ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने बस गेंद के हिसाब से खेला।' तंजिद का यह शतक बांग्लादेश के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट क्रिकेट में किसी बांग्लादेशी बल्लेबाज का इससे पहले शतक नहीं आया था। उनकी इस ऐतिहासिक पारी ने मेहमान टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट जीत की उम्मीद भी मजबूत कर दी है। तंजिद हसन व्हाइट-बॉल क्रिकेट में तमीम इकबाल के बाद बांग्लादेश की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। तमीम की तरह ही एक आक्रामक बाएं हाथ के ओपनर तंजिद ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में एक अर्धशतक बनाया था, जो शीर्ष स्तर के क्रिकेट में उनका पहला कदम था। इसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए बांग्लादेश टीम से बाहर होना पड़ा। उन्होंने बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शहरयार नफीस के साथ अपनी बल्लेबाजी पर काम किया और फिर 2023-24 बीपीएल सीजन में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें वापसी करने में मदद मिली। तंजिद को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरी तरह से पैर जमाने में 2025 तक का समय लगा। एक कैलेंडर वर्ष में टी20 अंतरराष्ट्रीय में उनके द्वारा बनाए गए 775 रन, किसी भी बांग्लादेशी बल्लेबाज द्वारा एक साल में बनाए गए सबसे अधिक रन हैं। उनके 135.25 के स्ट्राइक रेट ने भी टीम के आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने के फैसले में बड़ी भूमिका निभाई। वह हर मौके पर छक्के लगाने की कोशिश करते थे, जो बांग्लादेश के बल्लेबाजों के बीच एक नया और सकारात्मक बदलाव था। राजनीतिक कारणों से टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले सकी, लेकिन इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के खिलाफ 2-1 से जीती गई वनडे सीरीज में तंजिद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया। ढाका के उत्तर-पश्चिम में स्थित एक छोटे से शहर बोगरा में एक जनवरी, 2000 को जन्मे तंजिद को क्रिकेट खेलने के लिए अपने पिता को मनाना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने राजशाही में बांग्ला ट्रैक क्रिकेट अकादमी में कुछ समय बिताया। वह 2020 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली बांग्लादेशी टीम का हिस्सा थे, जहां उन्होंने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 80 रन बनाए थे।

कैंसर से बेटियों की सुरक्षा, एचपीवी टीकाकरण अभियान में देवरिया ने बढ़ाये कदम

डीएम मधुसूदन हुल्गी ने अभिभावकों और शिक्षकों से की जन-जागरूकता की अपील

निजी अस्पतालों में 4,000 रुपये कीमत वाला सुरक्षा कवच शासन की पहल से हुआ निःशुल्क

देवरिया।

महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने और जनपद की किशोरियों को सेहतमंद भविष्य देने की दिशा में जिला प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे 14 वर्ष पूर्ण कर चुकीं तथा 15 वर्ष से कम आयु की सभी पात्र बालिकाओं को एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) का टीका समय से जरूर लगवाएं। उन्होंने अभिभावकों, प्रधानाचार्यों और नागरिक समाज से इस अभियान को जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया है।

वैधानिक और चिकित्सीय अध्ययनों के हवाले से जिलाधिकारी ने बताया कि एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को लगभग 90 प्रतिशत तक कम कर देती है। यह टीका पूरी तरह सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। बाजार में तथा निजी अस्पतालों में इस वैक्सीन की कीमत लगभग चार हजार रुपये है, जिसे प्रदेश सरकार द्वारा पात्र बालिकाओं को स्वास्थ्य केंद्रों पर पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

कलेक्ट्रेट प्रशासन की देखरेख में अब तक जिले की 19,440 बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण पूरा किया जा चुका है। सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दैनिक स्तर के साथ-साथ प्रत्येक बुधवार और शनिवार को नियमित टीकाकरण सत्रों में एएनएम द्वारा यह सेवा दी जा रही है।

जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों, आशा-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवी संगठनों से समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी पात्र किशोरी इस सुरक्षा तंत्र से वंचित न रहे।

ज़मीनी विवादों का हाईटेक समाधान

रोवर तकनीक से नापी गई ज़मीन, मौके पर निपटे मामले

देवरिया।

राजस्व मामलों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के लिए जिला प्रशासन ने आधुनिक तकनीक और स्थलीय सत्यापन का रुख अपनाया है। शुक्रवार को जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने सलेमपुर तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर राजस्व व्यवस्थाओं और भूमि पैमाइश का जायजा लिया। इस दौरान ग्राम पुरैना में आधुनिक रोवर पद्धति का उपयोग कर चक रोड और धारा 24 से संबंधित भूमि की पैमाइश कराई गई। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने करौता और पुरैना में स्टांप मूल्यांकन का धरातलीय निरीक्षण किया, वहीं ग्राम मुसैला में काश्तकारों को अंश निर्धारण के प्रमाण पत्र वितरित किए। कलेक्ट्रेट प्रशासन का जोर इस बात पर है कि सीमांकन और

प्रशासन ने आईजीआरएस शिकायत का मौके पर कराया निस्तारण

सीमा विवादों में पारंपरिक फीते के बजाय रोवर जैसी सटीक तकनीक का इस्तेमाल हो, जिससे पैमाइश में त्रुटि की गुंजाइश न रहे और विवादों का स्थायी समाधान निकल सके। दूसरी ओर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रेम नारायण सिंह ने रुद्रपुर तहसील के ग्राम तारासारा पहुंचकर आईजीआरएस पर प्राप्त रामदरश पुत्र रामरेखा की शिकायत की खुद जांच की। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67-ए के तहत भू-विनियमितीकरण के इस मामले में एडीएम ने उपजिलाधिकारी रुद्रपुर को तत्काल वाद दर्ज कर प्रकरण निस्तारित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही एडीएम ने ग्राम नगवा खास में भी रोवर प्रणाली से भूमि सीमांकन कराया।

देवरिया में 'तिरंगा यात्रा' के दौरान भीषण गर्मी से बिगड़ी स्थिति, 40 से ज्यादा छात्राएं बीमार, अस्पताल में भर्ती

देवरिया । स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 'तिरंगा यात्रा' के दौरान एक बड़ा हादसा सामने आया है। रैली के दौरान कड़ाके की धूप और भीषण गर्मी के कारण 40 से अधिक स्कूली छात्राएं बीमार पड़ गईं जिन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह घटना गुरुवार (13 अगस्त) को घटी। छात्राओं का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह तेज़ गर्मी और धूप को बताया। मार्च के दौरान स्कूली छात्राओं को चक्कर आने की शिकायत हुई जबकि कुछ छात्राएं स्टेडियम पहुंचने के बाद बेहोश हो गईं जहां रैली खत्म हुई थी। वहीं अधिकारियों ने बताया कि स्टेडियम में कई एम्बुलेंस भेजी गईं और प्रभावित छात्राओं को महर्षि देवराहा बाबा ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया।

स्वतंत्रता दिवस से पहले मिलावट पर सख्ती: मिठाई दुकानों के साथ आवासीय स्कूल के किचन की जांच

दाल, चावल, रोटी व चाय का सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा

देवरिया।

आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की शुद्धता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देश पर शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच एवं जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान मिष्ठान प्रतिष्ठानों से लड्डू, समोसा, जलेबी और खोया के पांच नमूने एकत्र कर परीक्षण के लिए भेजे गए। अभियान के तहत सहायक आयुक्त (खाद्य) हितेंद्र मोहन त्रिपाठी के नेतृत्व में अधिकारियों ने व्यापारियों और उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों के सही रखरखाव और स्वच्छता के मानकों के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही, मेहरौना स्थित सर्वोदय आवासीय विद्यालय के भोजन में गड़बड़ी से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विद्यालय के किचन में सीधे पहुंचकर खाद्य सामग्रियों की जांच की।

टीम ने मौके से पके भोजन में इस्तेमाल होने वाले दाल, चावल, तैयार रोटी और चाय के नमूने सील किए, जिन्हें लैब में जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारियों ने रसोइयों को स्वच्छता और सुरक्षा मानकों के पालन के कड़े निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि लैब रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू पाल, घनश्याम वर्मा, श्रीराम यादव, रामसिंगार, प्रेम चंद तथा नेहा त्रिपाठी शामिल रहे।

न्यायालय के आदेश पर जीआरपी ने 15 लावारिस शराब के माल का कराया निस्तारण

भटनी देवरिया।

राजकीय रेलवे पुलिस थाना भटनी ने माल मुकदमाती निस्तारण अभियान के तहत शुक्रवार को 15 लावारिस शराब के माल का नियमानुसार विनिष्टीकरण कराया। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्र के निर्देशन और सीओ रेलवे सर्किल बलिया सवि रत्न गौतम के पर्यवेक्षण में हुई। थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार मौर्य ने न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर नायब तहसीलदार सलेमपुर हरि प्रसाद के नेतृत्व में गठित टीम की मौजूदगी में शराब का विनिष्टीकरण कराया। जीआरपी भटनी व देवरिया पुलिस की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया वीडियो फोटोग्राफी के साथ संपन्न की गई। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार की गई।

71 गांवों की बदलेगी विकास की तस्वीर, मास्टर प्लान तय करेगा भविष्य

मुरादाबाद। शहर के विस्तार के साथ अब आसपास के 71 राजस्व गांवों के विकास की दिशा भी बदलने जा रही है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) के प्रस्तावित विस्तारित विकास क्षेत्र के करीब 146 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए नया मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। विस्तारित क्षेत्र में इन दिनों फील्ड सर्वे और तकनीकी अध्ययन चल रहा है। इसमें आबादी, सड़क नेटवर्क, वर्तमान भू-उपयोग, जल निकासी, सार्वजनिक सुविधाओं, औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों और विकास की संभावनाओं का आकलन किया जा रहा है। प्रस्तावित विकास क्षेत्र में अमरोहा, कांठ, मुरादाबाद और संभल तहसील के कुल 71 गांव शामिल हैं। मास्टर प्लान में वर्तमान औद्योगिक इकाइयों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आवासीय क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जा रहा है। मास्टर प्लान लागू होने के बाद भवन मानचित्र, नई कॉलोनियों, आवासीय परियोजनाओं, औद्योगिक इकाइयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों समेत विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति निर्धारित भू-उपयोग के अनुरूप ही होगी। ऐसे में इन गांवों में जमीन खरीदने और निवेश करने वालों की नजर भी प्रस्तावित मास्टर प्लान पर टिकी है। अधिकारियों और विशेषज्ञों के अनुसार, करीब 146 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए तैयार हो रहा यह मास्टर प्लान मुरादाबाद के नियोजित शहरी विस्तार, आधारभूत सुविधाओं और संतुलित भूमि उपयोग की भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।

मईल बाजार के मेडिकल स्टोर पर औषधि निरीक्षक की छापेमारी, दवाओं की खरीद-बिक्री पर रोक

देवरिया।

जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में औषधि निरीक्षक राघवेन्द्र सिंह ने मईल बाजार स्थित बरनवाल मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर निरीक्षण किया। इस दौरान कई अनियमितताएं सामने आने पर मेडिकल स्टोर में दवाओं के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान की प्रोपराइटर अर्चना बरनवाल अनुपस्थित मिलीं। नियमित विक्रय अभिलेख और कैश मेमो जारी नहीं किए जा रहे थे। शिड्यूल एच एवं एच-1 दवाओं का रिकॉर्ड भी मौके पर

नहीं मिला। एक्सपायर्ड दवाओं को अलग रखने की व्यवस्था और पशुओं की दवाओं के पृथक भंडारण के लिए निर्धारित लेबल भी नहीं पाए गए। इसके अलावा कम तापमान पर रखी जाने वाली दवाओं के लिए फ्रिज की व्यवस्था नहीं थी। औषधि निरीक्षक ने मेडिकल स्टोर से तीन दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, स्टोर में मौजूद 13 औषधियों के क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण आख्या अग्रिम कार्रवाई के लिए सहायक आयुक्त (औषधि), गोरखपुर मंडल को भेजी गई है।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में 27.2% बढ़कर 652.86 करोड़ रुपए पर

नई दिल्ली। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण बनाने वाली प्रमुख कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड (एलजीईआई) का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2026-27 की जून तिमाही में 27.2 प्रतिशत बढ़कर 652.86 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 513.25 करोड़ रुपए था। एलजीईआई ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी की परिचालन से आय चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 15.5 प्रतिशत बढ़कर 7,233.35 करोड़ रुपए हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6,262.94 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने बयान में कहा कि सूचीबद्ध होने के बाद उसने जून तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया। यह वृद्धि बिक्री की मात्रा और उत्पादों के बेहतर मूल्य मिश्रण से प्रेरित रही। एलजीईआई ने कहा कि घरेलू मांग के साथ-साथ उसके निर्यात कारोबार में भी वृद्धि दर्ज की गई। उपभोक्ताओं में अधिक सुविधाओं वाले, उच्च मूल्य और ऊर्जा दक्ष उत्पादों की ओर बढ़ते रुझान से इसे समर्थन मिला। कंपनी का कुल खर्च पहली तिमाही में 14.25 प्रतिशत बढ़कर 6,450 करोड़ रुपए हो गया। एलजीईआई ने कहा, ''भू-राजनीतिक और व्यापक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हम मूल्य निर्धारण में अनुशासन, परिचालन दक्षता और स्थानीयकरण के माध्यम से अपने लाभ मार्जिन को बनाए रखने की दिशा में काम कर रहे हैं।''

भारत के सात राज्य 2031 तक 1380 नए जीसीसी और 12 लाख रोजगार का लक्ष्य लेकर चल रहे, रिपोर्ट में दावा

नई दिल्ली । रियल एस्टेट सलाहकार सीबीआरई की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित सात भारतीय राज्य 2031 तक 1380 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इन केंद्रों से करीब 12 लाख अतिरिक्त रोजगार पैदा होने का लक्ष्य है। सीबीआरई (कोल्डवेल बैंकर रिचर्ड एलिस) ने शुक्रवार को 'द पॉलिसी एडवांटेजः पावरिंग इंडियाज जीसीसी ग्रोथ' नामक अपनी रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट भारत में जीसीसी के विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर केंद्रित है। रिपोर्ट बताती है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, केरल, हरियाणा और मध्य प्रदेश इन सात राज्यों में करीब 1380 जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य है। इनका कुल लक्ष्य 2031 तक लगभग 1.18 दस लाख रोजगार सृजित करना है। सीबीआरई के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी- भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य पूर्व व अफ्रीका, अंशुमान मैगजीन ने कहा कि राज्य

सरकारों ने समर्पित जीसीसी नीतियों को औपचारिक रूप देने में अभूतपूर्व गति दिखाई है। उन्होंने बताया कि यह भारत के वाणिज्यिक रियल एस्टेट परिदृश्य में पहले कभी नहीं देखा गया। रिपोर्ट यह दर्शाता है कि ये केंद्र अब भारत की सेवा अर्थव्यवस्था का एक मामूली हिस्सा नहीं हैं। बल्कि, वे एक केंद्रीय स्तंभ बन गए हैं, जिनकी मेजबानी के लिए राज्य सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। राज्य लक्षित प्रोत्साहन, तेज अनुमोदन और दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा प्रतिबद्धताओं के माध्यम से ऐसा कर रहे हैं। कर्नाटक 500 जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिससे 3.5 लाख रोजगार पैदा होंगे। महाराष्ट्र का लक्ष्य 200 जीसीसी के साथ 4 लाख नए रोजगार का अवसर पैदा करना है। राजस्थान 200 से अधिक जीसीसी और 1.5 लाख रोजगार की संभावना देख रहा है। गुजरात 250 से अधिक जीसीसी का लक्ष्य बना रहा है, जिससे 50,000 रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। केरल 80 जीसीसी का लक्ष्य लेकर 1.6 लाख रोजगार पैदा करने का इरादा रखता है। हरियाणा सरकार 100 से अधिक जीसीसी का लक्ष्य बना रही है, जिससे 30,000 रोजगार सृजित होंगे। इसी तरह, मध्य प्रदेश 50 से अधिक जीसीसी और 37,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। सीबीआरई ने बताया कि तमिलनाडु ने जीसीसी कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पेश किए हैं। तेलंगाना और दिल्ली ने जीसीसी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे अपनाए हैं। कई अन्य राज्य भी इस क्षेत्र के लिए नीतिगत ढांचे तलाश रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जीसीसी ने 2022 और 2026 के पहले छह महीनों के बीच भारत के शीर्ष नौ शहरों में 123 दस लाख वर्ग फुट से अधिक कार्यालय स्थान पट्टे पर लिया है। यह आंकड़ा जीसीसी क्षेत्र में मजबूत वृद्धि और विस्तार को दर्शाता है। राज्य सरकारों की नीतियां इस वृद्धि को और गति देंगी। भारत वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा है। यह देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी; सेंसेक्स 300 अंक टूटा, निफ्टी 24,350 से नीचे

नई दिल्ली । शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को झटका लगा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में खुले। कच्चे तेल की कीमतें स्थिर होने के बावजूद बाजार सीमित दायरे में रहा। सेंसेक्स करीब 300 अंक गिरकर 77,800.37 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 65.85 अंक की गिरावट के साथ 24,330.00 के स्तर पर आ गया। यह गिरावट बाजार में निवेशकों की चिंता को दर्शाती है। ट्रेंट और हिंडाल्को जैसी कंपनियों के शेयरों में 2 फीसदी की बड़ी गिरावट देखी गई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक संकेतों का भी असर भारतीय बाजार पर पड़ा। शुक्रवार को सेंसेक्स 279.59 अंक यानी 0.35 फीसदी की गिरावट के साथ 77,800.37 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 65.85 अंक या 0.27 फीसदी की गिरावट आई। यह 24,330.00 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। दोनों प्रमुख सूचकांक लगातार सीमित दायरे में बने हुए हैं। वैश्विक बाजारों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। टोक्यो समय अनुसार सुबह 11:47 बजे एसएंडपी 500 फ्यूचर्स में मामूली बदलाव आया। जापान का टॉपिक्स 0.7 फीसदी की वृद्धि के साथ बंद हुआ। वहीं, ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/ एएसएक्स 200 और हांगकांग का हैंग सेंग क्रमशः 0.8 फीसदी और 0.7 फीसदी नीचे गिरे। शंघाई कंपोजिट में भी 0.2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जबकि यूरो स्टॉक्स 50 फ्यूचर्स 0.3 फीसदी बढ़ा। डॉलर इंडेक्स 7 अगस्त को 99.9 के आसपास कारोबार कर रहा था। अमेरिकी मुद्रास्फीति के नरम आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व की सितंबर में दर वृद्धि की उम्मीदों को कम कर दिया। जुलाई में अमेरिकी उत्पादक कीमतें अपरिवर्तित रहीं। यह 5 अगस्त की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट के बाद हुआ। इससे व्यापक मुद्रास्फीति दबाव सीमित होने का संकेत मिला। बाजार अब सितंबर में 25 आधार अंक की वृद्धि की करीब 35 फीसदी संभावना जता रहे हैं। यह 31 जुलाई को 55 फीसदी से कम है। मुद्रास्फीति के नरम पड़ने से पश्चिम एशिया संघर्ष और उच्च ऊर्जा लागत का प्रभाव कम होने का संकेत मिलता है। फिर भी, होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के संभावित समझौते पर अनिश्चितता मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए जोखिम बनी हुई है।

प्याज कीमतों में 25% का इजाफा, सितंबर की बारिश पर टिकी आगे की कीमतें

प्याज की बढ़ती कीमतें फिर रुलाने लगी हैं। देश की बड़ी मंडियों में शुमार लासलगांव में पिछले हफ्ते प्याज की थोक कीमतों में 25 फीसदी की तेजी आई है। बुधवार को लासलगांव एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में प्याज का औसत भाव बढ़कर 27 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, जबकि 5 अगस्त को यह 21.50 रुपए प्रति किलोग्राम था। अच्छी गुणवत्ता वाले प्याज की कीमत भी 24 रुपए से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। कीमतों में इस तेजी के बीच केंद्र सरकार सितंबर के पहले सप्ताह से बफर स्टॉक से प्याज बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। सरकार का उद्देश्य बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखना और बाजार में आपूर्ति बढ़ाना है। हालांकि, इस साल सरकार द्वारा न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य में सात बार बढ़ोतरी के बावजूद करीब 2 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले प्याज की खरीद लगभग 25 फीसदी कम रहने का अनुमान है। व्यापारियों के मुताबिक दक्षिण भारत से आने वाली खरीफ प्याज की फसल में देरी हो रही है। महाराष्ट्र में मानसून देर से पहुंचने के कारण खरीफ की बुवाई प्रभावित हुई, जिससे नासिक क्षेत्र से नई फसल की आवक भी देर से होने की संभावना है। फिलहाल देश में प्याज की आपूर्ति मुख्य रूप से मार्च-अप्रैल में भंडारित की गई रबी फसल से हो रही है। यह अक्टूबर तक बाजार का प्रमुख स्रोत रहती है। इसके साथ कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आने वाली शुरुआती खरीफ फसल आपूर्ति को सहारा देती है। अक्टूबर के बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों से खरीफ प्याज की बड़ी आवक शुरू होती है। महाराष्ट्र के प्याज निर्यातक दानिश शाह के अनुसार, आने वाले कुछ हफ्तों में कीमतों में बड़ी

तेजी की संभावना कम है और बाजार स्थिर रह सकता है। हालांकि, सितंबर का मौसम आगे की कीमतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। अगर सितंबर में भारी बारिश से दक्षिण भारत की नई फसल प्रभावित होती है, तो प्याज की कीमतों पर फिर से तेजी का दबाव बन सकता है। वहीं, मौसम अनुकूल रहा और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल बाजार में पहुंची, तो आपूर्ति सुधरने से कीमतों पर नियंत्रण बना रह सकता है। व्यापारियों का कहना है कि रबी प्याज के उत्पादन और भंडारण में बड़ी कमी नहीं है लेकिन इस साल खराब मौसम का असर फसल की गुणवत्ता पर पड़ा है। इसका असर केवल भारत में ही नहीं, बल्कि वैश्विक प्याज बाजार में भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर, आने वाले दिनों में सरकारी बफर स्टॉक की बिक्री से कीमतों को राहत मिल सकती है लेकिन सितंबर में मौसम और दक्षिण भारत से खरीफ प्याज की आवक यह तय करेगी कि बाजार में तेजी आगे जारी रहती है या कीमतें स्थिर होती हैं।

इक्विटी डेरिवेटिव्स में छोटे ट्रेडर्स को बड़ा झटका, 9.6 अरब डॉलर का नुकसान

नई दिल्ली । भारत में छोटे और रिटेल ट्रेडर्स के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कारोबार में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मार्च 2026 में समाप्त वित्त वर्ष के दौरान रिटेल निवेशकों का इक्विटी डेरिवेटिव्स में कुल नुकसान करीब 9.61 अरब डॉलर यानी 916.85 अरब रुपए रहा। हालांकि, यह नुकसान पिछले वित्त वर्ष के करीब 1.12 लाख करोड़ रुपए के नुकसान से कम है। सरकार ने संसद में यह जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की लिखित जानकारी के मुताबिक, इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने वाले निवेशकों की संख्या भी घटकर 80 लाख से कम रह गई, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा करीब 98 लाख था।

9 में से 10 रिटेल ट्रेडर्स को हुआ था नुकसान

रिटेल निवेशकों के लगातार नुकसान को देखते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने डेरिवेटिव्स कारोबार पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। सेबी के एक अध्ययन में पाया गया था कि हर 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स को डेरिवेटिव्स में नुकसान हुआ। इसके बावजूद यह लगातार पांचवां साल रहा जब व्यक्तिगत निवेशकों को F&O कारोबार में नुकसान उठाना पड़ा। इससे यह सवाल भी उठ रहा है कि नियामकीय सख्ती के बावजूद रिटेल निवेशकों को जोखिम भरे डेरिवेटिव्स कारोबार से दूर रखना इतना मुश्किल क्यों है।

सेबी ने कड़े किए कई नियम

रिटेल भागीदारी और सट्टेबाजी पर

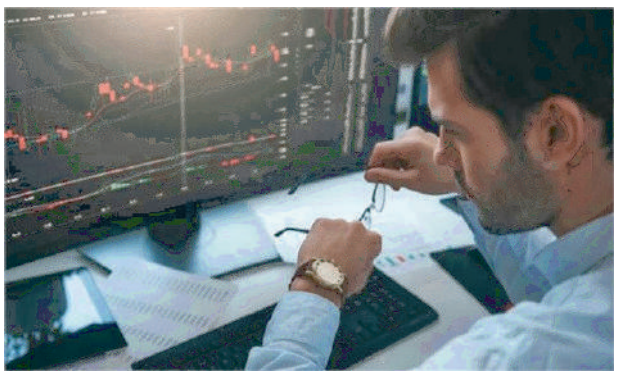

लगाम लगाने के लिए सेबी ने डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का आकार बढ़ाने, पोजिशन लिमिट कड़ी करने और कई अन्य सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले महीने प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स और स्टॉक ब्रोकरों के लिए फंडिंग से जुड़े नियम भी सख्त किए। इन कदमों का असर स्टॉक एक्सचेंजों की ट्रेडिंग गतिविधियों पर भी दिखाई दे रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध फ्यूचर्स और ऑप्शंस का औसत दैनिक नॉशनल टर्नओवर जुलाई में जून की तुलना में 23 फीसदी घटकर 214 लाख करोड़ रुपए रह गया। यह करीब 17 महीनों का निचला स्तर है।

रिटेल ट्रेडर्स की हिस्सेदारी फिर बढ़ी

दिलचस्प बात यह है कि सख्ती के बावजूद इक्विटी डेरिवेटिव्स में रिटेल निवेशकों का प्रभाव बढ़ा है। ह्स्श्र के आंकड़ों के अनुसार, इन कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग का करीब 31 फीसदी हिस्सा व्यक्तिगत निवेशकों के पास है, जो पिछले साल 26 फीसदी था। F&O में कम रकम के जरिए शेयरों की कीमतों पर दांव लगाने का मौका मिलता है, जिससे यह सेगमेंट रिटेल निवेशकों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है।

बड़े ट्रेडर्स पर भी पड़ा असर

नियामकीय सख्ती और बढ़ती ट्रेडिंग लागत ने बड़े खिलाड़ियों की गतिविधियों को भी प्रभावित किया है। NSE पर प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, जिनमें हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म भी शामिल हैं, की नॉशनल डेरिवेटिव्स टर्नओवर में हिस्सेदारी जून में घटकर 58.1 फीसदी रह गई, जबकि पिछले साल यह 60 फीसदी से अधिक थी। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने मार्च में कहा था कि नियामक इक्विटी डेरिवेटिव्स में अत्यधिक सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के लिए डेटा आधारित और संतुलित दृष्टिकोण अपनाएगा। फिलहाल उसका मुख्य फोकस कम अवधि वाले इंडेक्स ऑप्शंस पर है यानी नियमों की सख्ती से ट्रेडिंग गतिविधि जरूर कम हुई है लेकिन रिटेल निवेशकों का F&O के प्रति आकर्षण और उनका नुकसान अब भी बाजार नियामक के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।